



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266514  
CG-DL-E-29092025-266514

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 264]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम  
मामला सं. एडी(ओआई) - 25/2024  
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रिसोर्सिनॉल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/27/2024 - डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण

तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियमावली या नियमावली के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, अतुल लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, चीन जन. गण. और जापान (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) से रिसोर्सिनाॅल (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर 2024 की अधिसूचना सं. 6/27/2024 - डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन. गण. और जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई है ताकि संबद्ध वस्तुओं के किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### क. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:
  - क. प्राधिकारी ने नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में सूचित किया।
  - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया।
  - ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पत्तों के अनुसार, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
  - घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहां भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई।

- इ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
- i. एपेलोआ फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
  - ii. बुइपो इंटरनेशनल
  - iii. चांगशान हैचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
  - iv. ईस्ट वेस्ट कॉर्पोरेशन
  - v. फार्मासिनो कंपनी लिमिटेड
  - vi. हांगजो बेटर केमटेक लिमिटेड
  - vii. हांगजो वेरीकेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
  - viii. केन्को कॉर्पोरेशन
  - ix. शंघाई एमिनो-केम कंपनी लिमिटेड
  - x. सोजित्ज़ कॉर्पोरेशन
  - xi. सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड
  - xii. झेजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- छ. संबद्ध जांच शुरू होने पर, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके प्रतिक्रिया दी है:
- i. झेजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
  - ii. चांगशान हैचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
  - iii. झेजियांग डायस्टार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
  - iv. अमीनो-केम (एचके) कंपनी लिमिटेड
  - v. सोजित्ज़ कॉर्पोरेशन
  - vi. सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड
  - vii. बी.आर. केमिकल्स
  - viii. सोंगवोन इंटरनेशनल - जापान के.के.
  - ix. ईस्ट वेस्ट कॉर्पोरेशन
  - x. इनाबाटा एंड कंपनी लिमिटेड
  - xi. सुमिका केमटेक्स कंपनी लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को आयातक एवं उपयोगकर्ता प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक यूखचपस कर मांग की है।
- i. अनिल ऑर्गेनिक्स
  - ii. एरीज़ डाई केम इंडस्ट्रीज

- iii. एरीज़ ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- iv. एशियाटिक कलर-केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- v. ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- vi. कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- vii. केमस्पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- viii. एंडोर्स केमिकल्स एलएलपी
- ix. इनोवासिंथ टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड
- x. जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xi. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड
- xii. राजशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. रोहा डाई केम प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. सराफ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xv. सिद्धार्थ कलरकेम प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. सिंह प्लास्टिसाइज़र्स एंड रेजिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- xvii. सोमू ऑर्गेनो केम प्राइवेट लिमिटेड
- xviii. सोंगवॉन स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xix. एसआरएफ लिमिटेड
- xx. टेक्नो वैक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड

झ. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दाखिल करके प्रतिक्रिया दी है:

- i. ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज
- ii. सोमू ऑर्गेनो केम प्राइवेट लिमिटेड
- iii. ताओका केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- iv. टेक्नो वैक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड
- v. आल्प्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई, और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ट. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेन-देनों की उचित जांच किए जाने के बाद आयातों की मात्रा की गणना करने और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ठ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 7 मार्च 2025 को आयोजित की गई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत

करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित आवेदन करने और उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

- ड. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन होने के कारण, दिनांक 4 जुलाई 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित आवेदन और उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण करने व बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल थी।
- त. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए आवेदनों पर, साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण दिनांक 8 सितंबर 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात की टिप्पणियों की, जहां तक संगत समझा गया, जांच की है। कोई भी आवेदन जो केवल पिछले आवेदन की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- ध. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी संगत तर्कों और प्रदान की गई सूचनाओं पर, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं, विचार किया है।

- न. प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया गया।
- प. इस अधिसूचना में '\*\*\*' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- फ. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 83.69 है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया गया था।

*“विचाराधीन उत्पाद रिसोर्सिनॉल है। विचाराधीन उत्पाद को 1,3-बेंजीनडायोल; 1,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्ज़ीन; 3-हाइड्रॉक्सीफेनॉल; रिसोर्सिन मेटा-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्ज़ीन के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र  $C_6H_6O_2$  है। विचाराधीन उत्पाद की सीएस संख्या 108-46-3 है। विचाराधीन उत्पाद सफेद से लेकर हल्के सफेद रंग के गुच्छों के रूप में आता है और जल में घुलनशील है तथा व्युत्पन्नीकरण के लिए अनुकूल है।”*

#### ख.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं दिया है।

#### ख.2. घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध वस्तुओं के निर्माण हेतु तीन विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं: सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया; हाइड्रोपरऑक्सीडेशन प्रक्रिया; और एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया। घरेलू उद्योग सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया का उपयोग करता है। विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित संबद्ध वस्तुएं एक समान हैं, समान विनिर्देशों वाली हैं और समान उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती हैं।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं।

**ख.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

7. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद रिसोर्सिनॉल है, जिसे बाज़ार की भाषा में 1,3-बेंजीनडायोल; 1,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्ज़ीन; 3-हाइड्रॉक्सीफेनॉल; रिसोर्सिन मेटा-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्ज़ीन के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र  $C_6H_6O_2$  है।
8. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण तीन विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करके किया जा सकता है, जिनमें सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया, हाइड्रोपरऑक्सीडेशन प्रक्रिया और एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया शामिल हैं। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के उपयोग से अंतिम उत्पाद में कोई अंतर नहीं आता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित की गई संबद्ध वस्तुओं का उपयोग एक ही अनुप्रयोग के लिए और एक ही तरीके से किया जाता है, और विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किए गए अंतिम उत्पाद की विशेषताओं में कोई अंतर नहीं आता है।
9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 29 के अंतर्गत एचएस कोड 2907 2100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं, फिर भी अंतिम उत्पाद के विनिर्देश तुलनीय हैं और उनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इसी के आलोक में, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए गए उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जाता है।

**ग. घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति****ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

11. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**ग.2. घरेलू उद्योग के विचार**

12. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और उसके उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं के लिए संपूर्ण भारतीय उत्पादन शामिल है।
- ii. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।
- iii. आवेदक ने वर्ष 2021-22 के दौरान चीन में अपने संबंधित पक्षकार से संबद्ध वस्तुओं की नगण्य मात्रा का आयात किया है।
- iv. आवेदक को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाना चाहिए।

### ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” से तात्पर्य समग्र रूप से ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में लगे हैं या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, सिवाय इसके कि ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में “घरेलू उद्योग” शब्द का तात्पर्य शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच शुरू करने के लिए अतुल लिमिटेड द्वारा आवेदन दायर किया गया था, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक की चीन जन. गण. में एक संगत संस्था है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उसने अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान संगत पक्षकार से इन विचाराधीन उत्पादों की [\*\*\*] मीट्रिक टन की नगण्य मात्रा का आयात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये आयात जांच की अवधि से पहले किए गए थे और इस प्रकार, आवेदक घरेलू उद्योग के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र है।
15. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षा को पूरा करता है।

### घ. गोपनीयता

#### घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. आवेदक ने पृथक की गई बिक्री प्रवृत्तियों, परिशोधन व्यय, अनुक्रमित लागत विवरण आदि सहित प्रमुख आंकड़ों को छिपाया है, जिससे अत्यधिक गोपनीयता और पारदर्शिता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।



- ii. आवेदक ने देश-वार कीमत कटौती के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, और संचयी मूल्यांकन के आलोक में इसे अप्रासंगिक बताया है, जबकि प्राधिकारी ने स्वयं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील और जूट उत्पादों के मामले में देश-वार कीमत कटौती का प्रकटन किया है।
- iii. आवेदक जापान के लिए सामान्य मूल्य के स्रोत और कारखाना-बाह्य सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए तीसरे देश के निर्यात कीमत में किए गए समायोजन का प्रकटन करने में विफल रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के विपरीत, ब्लैक रोज़ की संबद्धता, विचाराधीन उत्पाद से जुड़ी इकाइयां, संगत कंपनी, वितरण चैनल और प्रभाव गणना से संबंधित सूचना व्यवसाय के प्रति संवेदनशील है और इसे साझा नहीं किया जा सकता।
- v. ब्लैक रॉक ने घरेलू उद्योग को कथित क्षति के संबंध में प्रतिक्रिया का उचित सारांश प्रदान किया है।

## घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

17. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना, जैसे बिक्री किए गए उत्पादों की सूची, को गोपनीय बताया है और व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।
- ii. अंतिम जांच परिणामों में सामान्यतः प्रकट की जाने वाली सूचना, जैसे वितरण चैनल और उन उत्पादकों का नाम, जिनसे संबद्ध वस्तुओं की खरीद की गई है, को गोपनीय बताया गया है।
- iii. कई हितबद्ध पक्षकारों ने ग्राहकों को इनवॉयस के बाद छूट प्रदान की है, लेकिन छूट के प्रकार को गोपनीय बताया है।
- iv. उचित तुलना करने के लिए समायोजन से संबंधित सूचना को गोपनीय बताया गया है।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में विलम्ब से अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- vi. जापान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किए जाने के संबंध में सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कर दी गई है।
- vii. चूंकि वर्तमान जांच में संचयन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, अतः देश-वार कीमत कटौती प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- viii. जापान के लिए तीसरे देश की निर्यात कीमत में समायोजन उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है।

## घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को, जहां भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है।

तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। गोपनीयता के संबंध में पक्षकारों के तर्कों की भी नीचे जांच की गई है।

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, गोपनीयता के संबंध में अनुरोध दाखिल करने की अंतिम तिथि अगोपनीय दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कई हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में विलंब से अनुरोध दाखिल किए हैं।
20. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक ने जापान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त सूचना आवेदन के परिशिष्ट के रूप में प्रदान की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित कर दी गई थी।
21. इस आवेदन के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने उत्तरों में कुछ सूचनाओं का प्रकटन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने द्वारा दावा की गई गोपनीयता को उचित ठहराया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना का प्रकटन न किए जाने से घरेलू उद्योग के हितों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।
22. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने देश-वार कीमत कटौती की सूचना प्रदान नहीं की है, घरेलू उद्योग ने दिनांक 7 दिसंबर 2024 के पत्र के माध्यम से इसे पहले ही प्रदान कर दिया है।
23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जापान की तृतीय देश निर्यात कीमत में किए गए समायोजन प्रदान नहीं किए हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में रिकार्ड में दर्ज सूचना को अगोपनीय रूप में प्रदान किया है। निर्यात कीमत के लिए किए गए समायोजन का प्रकटन पहले ही कर दिया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान के लिए सामान्य मूल्य सहयोगी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है। अतः, ऐसी सूचना का प्रकटन न किए जाने से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हितों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

### ड. विविध अनुरोध

#### ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
  - i. अनंतिम शुल्क उचित नहीं हैं क्योंकि आवेदक ने तीव्र आयातों या वित्तीय संकट के कारण क्षति की रोकथाम की तत्काल आवश्यकता प्रदर्शित नहीं की है।
  - ii. विगत जांचों में, 3 वर्ष की अवधि के लिए मानक शुल्क प्रभावी था। संबंधित आयात विगत शुल्क की अवधि के दौरान उचित मूल्य पर घरेलू बाजार में आए और घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा की मांग नहीं की। वर्तमान जांच में भी यही शुल्क लगाया जाना चाहिए।

- iii. विगत शुल्क निरर्थक हो गया था क्योंकि अमेरिकी संयंत्र के बंद होने के कारण बाजार में मांग व आपूर्ति का अंतर होने के कारण रिसोर्सिनाॅल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- iv. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो उसे केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए। विगत जांच में भी, कोई निर्णायक समीक्षा नहीं की गई थी, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी। दो वर्षों के बाद, एक निर्णायक समीक्षा की जा सकती है, और शुल्क केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब घरेलू उद्योग ने सभी उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति की हो और कैप्टिव खपत पर ध्यान केंद्रित न किया हो।
- v. आवेदक ने बिना उचित तर्क के डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। यह कम कीमत पर अधिक मात्रा में आयात का दावा करने का एक प्रयास है।
- vi. आवेदन में जांच शुरुआत किए जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं दी गई है।
- vii. जांच पाटन के पर्याप्त साक्ष्य के बिना शुरू की गई है क्योंकि आवेदक ने किसी तीसरे देश को जापान की निर्यात कीमत का विवरण नहीं दिया है।

## इ.2. घरेलू उद्योग के विचार

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, अंतरिम शुल्क को उचित ठहराने के लिए तीव्र क्षति दर्शाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, संदर्भ कीमत शुल्क, पाटन और क्षति की समस्या से निपटने के लिए अप्रभावी रहा है क्योंकि संदर्भ कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम रहा। उक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
- iii. प्राधिकारी डीजी सिस्टम्स या डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों की मांग कर सकते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की पुष्टि कर सकते हैं।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है कि आवेदन में जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है।
- v. 5 वर्ष से कम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यह वर्तमान मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां चीन सरकार ने जापान से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाकर अपने घरेलू बाजार में उचित मूल्य को बनाए रखा है। अन्य हितबद्ध पक्षकार, परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, दो वर्ष के बाद मध्यावधि समीक्षा के लिए प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

## इ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. इस तर्क के संबंध में कि जांच शुरुआत करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। प्रस्तुत साक्ष्य की प्रथम दृष्टया जांच किए जाने और प्रस्तुत साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता

के संबंध में स्वयं को पूरी तरह संतुष्ट किए जाने के बाद ही, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है जिससे कि प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाले कि उनके द्वारा प्रथम दृष्टया दिया गया मत गलत था।

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो वह दो वर्ष के लिए होना चाहिए और शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान मामले में शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है, तो वे उस अवधि और उसके स्वरूप पर विचार करेंगे जिसके लिए शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।
28. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के दायरे से बाहर आने वाले कुछ उत्पादों का भी आयात विचाराधीन उत्पाद पर लागू एचएस कोड के अंतर्गत किया जा रहा है। घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के पास डीजी सिस्टम्स या डीजीसीआई एंड एस के लेन-देन-वार आंकड़ों तक पहुंच नहीं है। घरेलू उद्योग ने अपने पास यथोचित रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य प्रदान किया है। तथापि, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा बाजार आसूचना आंकड़ों पर भरोसा करने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

#### सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

##### **इ.4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
  - i. चीन को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 दिनांक 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है। अतः, सामान्य मूल्य निर्धारण करने के लिए 'सरोगेट देश' निर्धारित किए जाने की प्रथा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ईसी-फास्टनर्स (चीन) में अपील निकाय की हाल की रिपोर्ट का संदर्भ लिया जा सकता है।
  - ii. भारत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में "पैक्टा संत सर्वदा" के सिद्धांत से बंधा है और उसे दिनांक 11 दिसंबर 2016 से चीन की पूर्ण बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थिति को मान्यता देनी होगी। वह निष्पादन में विफलता के औचित्य के रूप में घरेलू कानून का संदर्भ नहीं दे सकता।
  - iii. हाल तक, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इस समझ को साझा करते थे कि वर्ष 2016 के बाद चीन के साथ आर्थिक व्यवहार किया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ द्वारा जारी व्याख्यात्मक ज्ञापन यह भी दर्शाता है कि वह चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किए जाने के बाद केवल 15 वर्षों तक ही उसे एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में मानेगा।

- तथापि, एक द्विपक्षीय करार के आधार पर, व्हाइट हाउस चीन को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना जारी रखता है।
- iv. जापान के लिए सामान्य मूल्य और दोनों संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत, भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दायर की गई प्रश्नावली के उत्तरों पर आधारित होने चाहिए।
  - v. जापानी घरेलू बाजार पूर्णतः प्रतिस्पर्धी नहीं है और एससीसी के एकमात्र स्थापित निर्माता होने से प्रभावित है, इसलिए, उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य उसकी उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।vi. ताओका जापान रेसोर्सिनाॅल का उत्पादक नहीं है, बल्कि संशोधित रेसोर्सिनाॅल फॉर्मेलिडहाइड रेज़िन का निर्माण करता है। इसके अलावा, ताओका जापान ने जाँच अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया।
  - vii. आवेदक के मूल्य संबंधी दावे त्रुटिपूर्ण हैं, जिनमें सामान्य मूल्य की गणना बढ़ा-चढ़ाकर की गई है और समुद्री मालभाड़ा का समायोजन निराधार हैं।
  - viii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया पाटन मार्जिन बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। घरेलू उद्योग ने अपनी लागत और अन्य उत्पादकों के बीच अलग-अलग उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए कोई समायोजन किए बिना, अपनी लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

#### इ.5. घरेलू उद्योग के विचार

30. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित अनुरोध किया है।
  - i. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I, नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
  - ii. चूंकि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी लागू हैं, अतः चीन जन. गण. में उत्पादकों द्वारा यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।
  - iii. ईसी-फास्टनेर्स में अपील निकाय ने इस पर विशेष रूप से विचार नहीं किया कि अनुच्छेद 15(क) के संपूर्ण प्रावधान या केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 15 वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगे।
  - iv. सभी हाल की जांचों में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है।
  - v. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, यूरोपीय संघ और अमेरिका चीन जन. गण. की घरेलू बिक्री और लागत को अनदेखा कर रहे हैं। जबकि चीन ने इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय से संपर्क किया था, लेकिन बाद में उसे निलंबित कर दिया था।

- vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत, चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि चीन के उत्पादक यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि उनके घरेलू बाजार में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। चीन के उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का उत्तर भी दाखिल नहीं किया है।
- vii. आवेदन दाखिल करते समय उपलब्ध सूचना के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य प्रदान किया गया है।
- viii. जापानी उत्पादक का यह दावा कि बाजार की कीमत उसके एकमात्र उत्पादक होने के कारण प्रभावित होती है, जापानी उत्पादक द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को दर्शाता है। तथापि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जापान में उपभोक्ताओं या जापान में प्रतिस्पर्धा अधिकारियों ने इस तरह के दुरुपयोग की जांच की है। उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और लाभ का निर्धारण व्यापार के सामान्य क्रम में की गई बिक्री के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ix. निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समायोजन उपलब्ध सूचना के अनुसार हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- x. सुमितोमो केमिकल कंपनी द्वारा दायर प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके संगत पक्षकार, ताओका केमिकल कंपनी, वर्तमान जांच में भाग लेने में विफल रहे हैं। उक्त संस्था की वेबसाइट के अनुसार, यह विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है।
- xi. विदेशी उत्पादक इनवॉयस के बाद छूट प्रदान कर रहे हैं और ग्राहकों के साथ उनके प्रतिपूरक समझौते हैं। प्राधिकारी इसकी पुष्टि कर सकते हैं।
- xii. टेक्नो वैक्सकेम ने चीन के निर्यातक से रिसोर्सिन्नॉल का आयात किया है और उसी संस्था को डाउनस्ट्रीम उत्पाद का निर्यात किया है। जिस कीमत पर डाउनस्ट्रीम उत्पाद को चीन जन. गण. को निर्यात किया गया है वह उस कीमत से काफी कम है जिस पर उसने उसी उत्पाद को अन्य देशों को निर्यात किया है। इसके अलावा, टेक्नो वैक्सकेम ने चीन जन. गण. को डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्यात की तुलना में अधिक कीमत पर संबद्धवस्तु का आयात किया है।
- xiii. ब्लैक रोज़ द्वारा आयात की कीमत विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसका जापानी उत्पादकों के साथ एक विशेष व्यापारिक समझौता है। जापानी उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद की आयात कीमत, जब व्यापारियों से आयात किया जाता है, तो ब्लैक रोज़ के आयात की कीमत से बहुत कम होता है, जिसने उक्त उत्पाद को सीधे उत्पादक से आयात किया है। एससीसी के मूल्य की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह सीमा से अधिक न हो।
- xiv. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

#### इ.6. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 31. सुमितोमो केमिकल कंपनी ("एससीसी") द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार न किए जाने संबंधी अनुरोध के संबंध में, क्योंकि उसके संबंधित उत्पादक ने इसमें भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी

यह नोट करते हैं कि एससीसी का संगत पक्ष संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न नहीं है। अतः, उक्त उत्पादक को वर्तमान जांच में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

32. इस अनुरोध के संबंध में कि एक प्रतिपूरक समझौता है और उत्पादक इनवॉयस प्रक्रिया के बाद छूट प्रदान कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों की सत्यापित जानकारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।

33. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:

*“i) समान वस्तु के लिए, व्यापार के सामान्य क्रम में, तुलनीय कीमत, जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए हो, जैसा कि उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है, या*

*ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, तो सामान्य मूल्य या तो इस प्रकार होगा:*

*(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत, जब निर्यातक देश या क्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया जाता है, जैसा कि उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है; या*

*उक्त वस्तु की मूलता के देश में उत्पादन लागत, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभों के लिए उचित योग सहित, जैसा कि उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;*

*(ख) बशर्ते कि मूलता के देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित न हो या निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत न हो, सामान्य मूल्य मूलता के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।”*

34. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं:

- i. झेजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- ii. चांगशान हैचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- iii. झेजियांग डायस्टार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- iv. अमीनो-केम (एचके) कंपनी लिमिटेड
- v. सोजित्ज़ कॉर्पोरेशन
- vi. सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड
- vii. बी.आर. केमिकल्स
- viii. सोंगवोन इंटरनेशनल - जापान के.के.
- ix. ईस्ट वेस्ट कॉर्पोरेशन
- x. इनाबाटा एंड कंपनी लिमिटेड

xi. सुमिका केमटेक्स कंपनी लिमिटेड

## इ.7. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

### इ.7.1. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

35. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान इस प्रकार है :

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

- (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांच अधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है :
- (i) यदि जांच अधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।



- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
36. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और मूल्य की सूचना बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
37. वर्तमान मामले में किन्हीं भी सैम्पल उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को मूल्य के आधार पर या जहां यह संभव न हो, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया जाएगा। संबंधित देश और संबंधित उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा, और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना का उचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार

अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी भी समान मामले में की गई जांच का समय-सीमा के भीतर लेखा-जोखा लिया जाएगा। जांच में शामिल पक्षकारों को बिना किसी अनुचित विलंब के बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"

38. आवेदक ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में सूचीबद्ध आधारों के अलावा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। अतः, प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित, भारत में देय मूल्य के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

#### इ.7.2. चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

##### झेजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

39. जांच की अवधि के दौरान, झेजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड (होंगशेंग) ने भारत को \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें से \*\*\* मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। शेष मात्रा चांगशान हाइचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड (हाइचेंग केमिकल), और झेजियांग डायस्टार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (डायस्टार) के माध्यम से, और इसके बाद अमीनो-केम (एचके) कंपनी लिमिटेड (एमिनो एचके) और सोजितज़ कॉर्पोरेशन (सोजितज़) के माध्यम से निर्यात की गई है।

होंगशेंग □ → भारत में असंबंधित ग्राहक

होंगशेंग □ → हाइचेंग केमिकल (असंबंधित) □ → भारत में असंबंधित ग्राहक

होंगशेंग □ → डायस्टार (संबंधित) □ → अमीनो एचके (संबंधित) □ → सोजितज़ (असंबंधित) □ → भारत में असंबंधित ग्राहक

40. उपरोक्त सभी निर्यातकों और व्यापारियों ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग किया है। प्राधिकारी ने भारत में पहले असंबंधित ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। उत्पादक और निर्यातकों ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। डेस्क सत्यापन के बाद इन्हें अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा, संबंधित निर्यातकों/ व्यापारियों के घाटे को समायोजित किया गया है। भारत में असंबंधित ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर

पहुंच मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

#### **चीन जन. गण. में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

41. चीन के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **इ.7.3. जापान के लिए सामान्य मूल्य**

##### **सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य**

42. जांच की अवधि के दौरान, सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड (सुमितोमो) ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात किया है, जबकि घरेलू बाजार में \*\*\* मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा पर्याप्त है, जिससे कि घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सके। सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड ने घरेलू बाजार में संबंधित और असंबंधित ग्राहकों को समान वस्तु बेची है। संबंधित व्यापारियों के लिए, प्राधिकारी ने व्यापारियों द्वारा पुनः बिक्री कीमत पर विचार किया है।
43. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया का परीक्षण किया है। सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। एससीसी ने घरेलू बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, हैंडलिंग और लोडिंग शुल्क और क्रेडिट लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन डेस्क सत्यापन के बाद अनुमत किए गए हैं। इस प्रकार, कारखाना-बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।
44. इस अनुरोध के संबंध में कि एससीसी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित लाभ लिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू बाजार एससीसी के एकमात्र निर्माता होने के कारण प्रभावित होता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तथ्य का कोई सबूत नहीं है कि उक्त उत्पादक अपने घरेलू बाजार में अनुचित लाभ वसूल रहा है। सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुसार किया गया है।

### जापान में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

45. जापान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### इ.7.4.जापान के लिए निर्यात मूल्य

##### सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

46. सुमितोमो ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें से \*\*\* मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। शेष मात्रा बी.आर. केमिकल्स (बीआरसी) और ईस्ट वेस्ट कॉर्पोरेशन (ईस्ट वेस्ट), और सोंगवोन इंटरनेशनल - जापान के.के. (सोंगवोन) के माध्यम से निर्यात की गई है। सोंगवोन इंटरनेशनल - जापान के.के. ने बदले में, एक सहयोगी कंपनी, सोंगवोन स्पेशलिटी केमिकल्स-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सोंगवोन इंडिया) को वस्तुओं की बिक्री की है। निर्यात के माध्यमों का सारांश नीचे दिया गया है।

सुमितोमो → भारत में असंबंधित ग्राहक

सुमितोमो → बीआरसी (असंबंधित) → ईस्ट वेस्ट (असंबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

सुमितोमो → सोंगवोन (असंबंधित) → सोंगवोन इंडिया (सोंगवोन से संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

47. उपरोक्त सभी निर्यातकों, व्यापारियों और संबंधित आयातकों ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग किया है। प्राधिकारी ने पहले असंबंधित ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित किया है। इसके अलावा, सोंगवोन के संबंधित आयातक को हुए नुकसान के लिए समायोजन किया गया है। पक्षकारों ने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, हैंडलिंग और परिवहन शुल्क, वित्त/ बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

##### जापान में अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

48. जापान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### इ.8. पाटन मार्जिन

49. जैसा कि ऊपर दिया गया है, निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएस डॉलर/मी. टन)	(यूएस डॉलर/मी. टन)	(यूएस डॉलर/मी. टन)	(%)	(रेंज)
क	चीन जन गण					
1	झेजियांग होदगशेंग कैमिकल कं. लि.	***	***	***	***%	25-35
2	अन्य	***	***	***	***%	35-45
ख	जापान					
3	सुमिटोमो कैमिकल कं. लि.	***	***	***	***%	30-40
4	अन्य	***	***	***	***%	50-60

#### च. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

##### च.1. अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

50. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क्षति विश्लेषण के लिए 2020-21 को आधार वर्ष मानना गलत है क्योंकि इस अवधि के दौरान आईएनडीएसपीईसी के रेसोर्सिनाॅल संयंत्र के बंद होने और कोविड-19 के प्रभाव के कारण कीमतें असामान्य रूप से बहुत अधिक थीं।

- ii. वर्तमान मामले में संचयी आकलन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चीन से आयात 2022-23 तक बढ़ गया है, जबकि जापान से आयात में कमी आई है। इसके अलावा, जापान से आयात मूल्य चीन से आयात मूल्य से अधिक है।
- iii. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद जापान से आयात में कमी आई है, जो मात्रा क्षति के अभाव को दर्शाता है।
- iv. भारत में आयात की मात्रा में कमी आई है जबकि मांग में वृद्धि हुई है।
- v. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में हानि, यदि कोई हो, चीन से बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है।
- vi. आवेदक ने क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों के लिए मूल्य कटौती से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की है। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, कारण विश्लेषण पूरा नहीं किया जा सकता है।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई मूल्य कटौती 0-10% है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और आयातों के पहुँच मूल्य के बीच कोई महत्वपूर्ण मूल्य असमानता नहीं है।
- viii. ब्लैक रोज़ की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से बहुत अधिक हैं।
- ix. आवेदक ने बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर करते हुए अपनी कीमतों में आक्रामक रूप से कमी की है।
- x. आवेदक आधार वर्ष से लगातार अपनी कीमतों में कमी कर रहा है, लेकिन बाजार हिस्सेदारी हासिल नहीं कर रहा है, जो दर्शाता है कि ग्राहक उच्च कीमतों पर आयात करने को तैयार हैं क्योंकि आवेदक एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है।
- xi. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि अन्य उत्पादकों की लागत में बदलाव के अनुरूप नहीं है। लागत का 50-60% हिस्सा बनाने वाले कच्चे माल, बेजीन की कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- xii. जापान से आने वाली संबद्ध वस्तुओं की कीमतें अतुल और चीन से आने वाली संबद्ध वस्तुओं, दोनों की कीमतों की तुलना में स्थिर रहीं। घरेलू उद्योग और चीनी निर्यातकों द्वारा बनाए गए मूल्य दबाव के कारण, एससीसी को जाँच अवधि के दौरान अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- xiii. आवेदक माँग में गिरावट के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा।
- xiv. अतुल अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन और निर्यात पर अधिक केंद्रित रहा है और भारतीय बाजार की आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता है। यहाँ तक कि जब पाटनरोधी शुल्क लागू थे, तब भी अतुल की बाजार हिस्सेदारी 10-20% के दायरे में रही।
- xv. घरेलू उद्योग ने उत्पादन और क्षमता उपयोग सहित प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखाया है, जिससे भौतिक क्षति के दावे कमज़ोर हुए हैं। आयात में गिरावट आई जबकि

- घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई, जो आयात और घाटे के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं दर्शाता है।
- xvi. घरेलू उद्योग के भंडार में वृद्धि हुई है क्योंकि उसने माँग में गिरावट के बावजूद अपने उत्पादन में वृद्धि जारी रखी है।
- xvii. कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है, जबकि वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी इसकी जाँच कर सकते हैं।
- xviii. शुद्ध अचल संपत्तियों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में कमी आई है।
- xix. नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई है, जबकि स्थापित क्षमता अपरिवर्तित रही है। मूल्यहास और शुद्ध अचल संपत्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं।
- xx. लाभप्रदता में कमी आवेदक की आक्रामक व्यापार विकृत मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण है।
- xxi. प्राधिकारी को निजी उपयोग में लाई जाने वाली संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, उसका मूल्यांकन, बाजार में संबद्ध वस्तुओं को बेचने या निजी उपयोग में लाने के निर्णय और डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लाभप्रदता का सत्यापन करना चाहिए।
- xxii. घरेलू उद्योग की लागत प्रवृत्तियाँ वैश्विक पैटर्न से अलग हैं, जहाँ कच्चे माल की घटती कीमतें बढ़ती उत्पादन लागत के विपरीत हैं। बेहतर आर्थिक संकेतक, बैच उत्पादन की अक्षमताएँ और पुरानी तकनीक घाटे की व्याख्या करती हैं। घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक आम बैठक में भी इसे स्वीकार किया था।
- xxiii. आवेदक को अकुशल उत्पादन प्रक्रिया के कारण क्षति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सल्फोनेशन प्रक्रिया अत्यधिक पूंजी और श्रम-गहन प्रक्रिया है, इसमें उच्च निवेश लागत की आवश्यकता होती है, इसके उप-उत्पादों के माध्यम से कम लागत वाली वसूली होती है, उच्च उपयोगिता लागत और कम उपज होती है। इसकी तुलना में, एससीसी हाइड्रोपरऑक्सीडेशन प्रक्रिया का उपयोग करता है।
- xxiv. अप्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग को घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषता नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके पास अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने का विकल्प है। चूंकि प्रौद्योगिकी का विकास एक प्रासंगिक कारक है, इसलिए यह विचार किया जाना चाहिए कि अप्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- xxv. घरेलू उद्योग को क्षति कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत, बाजार की माँग में बदलाव या संचालन लागत में अकुशलता और इन्वेंट्री प्रबंधन में समस्याओं जैसे कारकों के कारण हो सकती है।

- x xxvi. लाभ में गिरावट मूल्यहास में वृद्धि के कारण बिक्री लागत में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आयात की कम मात्रा के बावजूद अपनी बिक्री कीमत कम कर दी।
- xxvii. मांग में गिरावट के कारण हुई क्षति को आयात के कारण नहीं माना जाना चाहिए। मांग में गिरावट का कारण भी नहीं बताया गया है।
- xxviii. आवेदक ने परिचालन स्थिरता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, क्योंकि उसकी वार्षिक रिपोर्ट 2020 में एक महीने के बंद की पुष्टि करती है।
- xxix. प्राधिकारी भौगोलिक स्थिति, कच्चे माल की सोर्सिंग में चुनौतियों, घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाने वाले उच्च उधार लागत जैसे अन्य कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं।
- xxx. रूस-यूक्रेन संकट जैसे कारक, जिनके कारण वैश्विक मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कच्चे माल और अप्रत्यक्ष सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाया हो सकता है।
- xxxi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति, 2017 में इंडस्पेक, यूएसए के बंद होने, जिसके कारण उत्पाद की कमी हुई और कीमत में वृद्धि हुई तथा 2018-2021 के बीच एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने जैसे घटनाक्रमों के बाद बाजार के सामान्य होने के कारण हुई है। कोविड के बाद, आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई जिससे कीमत सामान्य हो गई।
- xxxii. वैश्विक स्तर पर कीमतें कम हुई हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग चीन में पिरेली टायर कंपनी लिमिटेड को निर्यात करता है। इन निर्यातों की कीमतें 2021 से कम हो रही हैं और जांच अवधि के दौरान 4.99 डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं।
- xxxiii. दावा किया गया उच्च क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई उच्च लागत और गैर-हानिकारक मूल्य के कारण है।
- xxxiv. गैर-हानिकारक मूल्य को अन्य उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न उप-उत्पाद के मूल्य के बराबर उत्पन्न उप-उत्पाद की लागत के संबंध में समायोजित किया जाना चाहिए। हाइड्रोपरऑक्सीडेशन प्रक्रिया की लागत को दर्शाने के लिए उपयोगिताओं की लागत में 8-10% की कमी की जानी चाहिए।
- xxxv. नियोजित पूँजी पर 22% का प्रतिफल नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रतिफल नियोजित पूँजी के ऋण भाग पर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, वैश्विक मंदी के दौर में ऐसा प्रतिफल बहुत अधिक है। नियोजित पूँजी पर 22% का प्रतिफल, ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर, निवल संपत्ति पर 27.15% से 41.41% तक का प्रभावी लाभ दर्शाता है।
- xxxvi. क्षति-रहित मूल्य के निर्धारण के लिए 22% नियोजित पूँजी पर प्रतिफल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उद्योग में औसत प्रतिफल 10% से अधिक नहीं है। क्षति को दूर करने वाले मूल्य के निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ उस लाभ मार्जिन पर विचार करता



है जिस पर प्रतिस्पर्धा की सामान्य परिस्थितियों में और पाटन की अनुपस्थिति में उचित रूप से भरोसा किया जा सकता है।

- xxxvii. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987, 22% प्रतिफल पर विचार करने का आधार बनता है। हालाँकि, ऐसा आदेश भी मानता है कि निवल संपत्ति पर 14% का प्रतिफल दिया जा सकता है, या नियोजित पूँजी पर 22% का प्रतिफल दिया जा सकता है।
- xxxviii. अतीत में जब ब्याज दर 18% और कॉर्पोरेट कर की दर 40%-50% थी, तब 22% का रिटर्न उचित था। हालाँकि, अब जब ब्याज दर घटकर 10% और कॉर्पोरेट कर की दर 25% हो गई है, तो ऐसा रिटर्न अनुचित है।
- xxxix. ब्रिजस्टोन टायर निर्माण के मामले में, सी ई एस टी ए टी ने पाया कि नियोजित पूँजी पर 22% का रिटर्न अपना उचित नहीं है क्योंकि इससे क्षति मार्जिन बढ़ जाता है। ह्यूस्टन कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण के मामले में भी CESTAT ने इसी तरह का विचार व्यक्त किया था।

## च.2. घरेलू उद्योग के विचार

51. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रस्तुतियों के विपरीत, संचयी मूल्यांकन हेतु सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। अतः, प्राधिकारी क्षति का संचयी मूल्यांकन कर सकते हैं।
  - ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संबद्ध देशों के बीच आयातों की आवाजाही, मात्रा में परस्पर परिवर्तन प्रासंगिक नहीं हैं और मात्रा पर प्रभाव या क्षति की कमी नहीं दर्शाते हैं। अन्य किसी भी हितबद्ध पक्ष ने यह नहीं दर्शाया है कि संचयी मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - iii. देश में मांग-आपूर्ति का अंतर है। जब तक आयात मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा कर रहे थे, तब तक घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी। हालाँकि, कम कीमतों पर आयात में वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छिन गया है।
  - iv. जाँच अवधि के बाद आयात की मात्रा में और वृद्धि हुई है और इसने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छिन लिया है।
  - v. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
  - vi. जाँच अवधि के बाद कीमत कटौती में वृद्धि हुई है।
  - vii. कीमत कटौती विश्लेषण केवल जाँच अवधि के लिए प्रासंगिक है, क्षति अवधि के लिए नहीं।
  - viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कीमत कटौती अधिक नहीं है क्योंकि रेसोर्सिनाँल एक कमोडिटी उत्पाद है और घरेलू उद्योग आयात की कीमतों से मेल खाने के लिए बाध्य है।
  - ix. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में काफी गिरावट आई है। पहुँच कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में परिवर्तन के अनुरूप नहीं है।
  - x. भारत में पहुँच कीमत में वैश्विक स्तर पर निर्यात कीमत में गिरावट से अधिक गिरावट आई है।

- xi. घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत और संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत के बीच अंतर में कमी आई है।
- xii. घरेलू उद्योग को ब्लैक रोज की कीमतों या लागत संरचना या कीमतों की जानकारी नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, केवल निर्यातक की कीमत ही प्रासंगिक है, असंबंधित भारतीय व्यापारी की नहीं। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि भारतीय उद्योग निर्यातक की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है क्योंकि पाटन के अभाव में आयातक को किसी अन्य स्रोत से खरीद करने से कोई नहीं रोकता। संबंधित आयातक के मामले में भी, प्राधिकारी क्षति विश्लेषण के लिए पुनर्विक्रय मूल्य पर विचार नहीं करते हैं।
- xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक की क्षमता भारतीय मांग से कम है और इसलिए, उसके पास कीमतें कम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है।
- xiv. सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाती है कि कीमतें निर्यातकों द्वारा कम की गई थीं, न कि घरेलू उद्योग द्वारा।
- xv. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का हास कर दिया है और उनका न्यूनीकरण कर दिया है।
- xvi. क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है, जैसा कि कच्चे माल के आयात कीमत से स्पष्ट है।
- xvii. घरेलू उद्योग को अपने संयंत्र को चालू रखने और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि घरेलू उद्योग ने कीमतें कम नहीं की होतीं, तो उसे घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के मामले में नुकसान उठाना पड़ता।
- xviii. घरेलू उद्योग ने अपशिष्ट उपचार संयंत्र में निवेश करके अपनी लागत कम की है, जिसके परिणामस्वरूप रूपांतरण लागत में कमी आई है। यद्यपि रूपांतरण लागत में कमी आई है, घरेलू उद्योग को इस गिरावट से कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि उसे बिक्री कीमत में इस गिरावट से भी अधिक कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, एससीसी अपने घरेलू बाजार में भारी मुनाफा कमा रही है और इसलिए, भले ही वह निर्यात बाजार में घाटे में बेच रही हो, उसकी व्यवहार्यता अच्छी है। इस प्रकार, एससीसी ने भारत में कीमत कम कर दी है।
- xx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, शुल्क का मानक रूप अप्रभावी था क्योंकि मानक घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम था। पाटनरोधी शुल्क की अवधि के दौरान पाटन न होने के कारण घरेलू उद्योग अपने आर्थिक मापदंडों में सुधार करने में सक्षम रहा है।
- xxi. घरेलू उद्योग केवल संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचने के कारण ही अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा।
- xxii. जांच अवधि के बाद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- xxiii. 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग द्वारा धारित बाजार हिस्सेदारी बहुत कम है।
- xxiv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की भंडार धारण अवधि में वृद्धि हुई है।

- xxv. मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद भंडार में वृद्धि अपने आप में घरेलू उद्योग के लिए क्षति को स्थापित करती है। यदि भारत में कोई पाटन नहीं होता, तो घरेलू उद्योग अपने पूरे स्टॉक को समाप्त करने में सक्षम होता।
- xxvi. जांच अवधि में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।
- xxvii. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति मुनाफे, नकद मुनाफे, निवेश पर प्रतिफल और वृद्धि में गिरावट से स्पष्ट है।
- xxviii. जांच अवधि के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और गिरावट आई है।
- xxix. घरेलू उद्योग को ब्याज का प्रावधान करने से पहले ही घाटा हो गया है। इस प्रकार, इसने अपने ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई भी नहीं की है।
- xxx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा कोई आक्रामक व्यापार विकृत मूल्य निर्धारण नहीं किया जा रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर केवल तीन उत्पादक हैं और भारत में माँग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है।
- xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यदि निवेश पर प्रतिफल का निर्धारण आधार वर्ष के एनएफए को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो भी क्षति अवधि के दौरान इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी जाएगी।
- xxxii. वर्तमान स्थिति किसी भी नए निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। घरेलू उद्योग अपने संयंत्र के पूर्ण मूल्यहास के कारण ही अपना अस्तित्व बचा पाया है। नए निवेश की स्थिति में, उत्पादक निवेश पर कोई प्रतिफल अर्जित नहीं कर पाएगा।
- xxxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति का दावा आवेदक के वास्तविक अभिलेखों पर आधारित है। निर्यातकों ने अपने आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित नहीं किया है कि निर्यात कीमत में गिरावट लागत और उसके घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट के कारण है।
- xxxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग का पीबीडीआईटी, जिसमें मूल्यहास शामिल नहीं है, भी कम हुआ है। इस प्रकार, क्षति मूल्यहास में वृद्धि के कारण नहीं है। किसी भी स्थिति में, मूल्यहास घरेलू उद्योग का एक वास्तविक व्यय है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
- xxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, घरेलू उद्योग को हुई क्षति मांग में गिरावट के कारण नहीं है क्योंकि भारत में मांग आवेदक की क्षमताओं से कहीं अधिक है।
- xxxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताओं की पहचान की है। चूंकि क्षति अवधि के दौरान ऐसे कारकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आवेदक अतीत में लाभदायक था, इसलिए क्षति ऐसे कारकों के कारण नहीं है।
- xxxvii. यह दावा कि घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक अप्रचलित है, केवल एक बयान है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी तकनीक को अप्रचलित बनाने वाला एक भी कारक प्रदान नहीं किया है।
- xxxviii. एससीसी और आवेदक की तकनीक में अंतर अप्रासंगिक है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्ष भारत में पाटन कर रहे हैं, चाहे उनकी तकनीक कुछ भी हो।

- xxxix. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के कारण के रूप में 2020 में शटडाउन की ओर इशारा किया है, जो कोविड-19 के कारण था, क्षति का दावा जांच की अवधि में किया गया है, न कि 2020 में।
- xl. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, रूस-यूक्रेन संकट का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, सामान्य कारोबारी परिदृश्य में कच्चे माल की लागत में वृद्धि से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए। कीमतों में गिरावट भारत में पाटन के कारण है।
- xli. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि जांच अवधि की तुलना किसी भी पिछले वर्ष से करने पर होती है, न कि केवल आधार वर्ष से।
- xlvi. इस अनुरोध के विपरीत कि कीमतों में कमी बाजारों के सामान्य होने के कारण हुई है, संबद्ध देश के उत्पादक भारत में उत्पाद की पाटन कर रहे हैं, जिसके कारण भारत में कीमतें कम हो गई हैं।
- xlvi. आवेदक चीन में उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम रहा है क्योंकि चीन सरकार ने घरेलू बाजार में उचित मूल्य बनाए रखा है और जापान से चीन में आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है।
- xlv. क्षतिरहित कीमत अनुबंध III के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, अनुलग्नक III में प्राधिकारी से केवल आवेदक के वित्तीय आंकड़ों पर विचार करने की अपेक्षा की गई है।
- xlv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियोजित पूंजी पर प्रतिफल से संबंधित निवेदनों के लिए कृत्रिम ऋण इक्विटी अनुपात पर विचार किया है। वास्तविक अनुपात काफी भिन्न हो सकते हैं।
- xlvi. औषधि नियंत्रण आदेश, 1987 का संदर्भ उचित नहीं है क्योंकि यह उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि की अनुमति देता है। हालाँकि, प्राधिकारी कृत्रिम रूप से दबाई गई लागत पर विचार करता है और इसलिए, क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग की पूरी लागत की वसूली की भी अनुमति नहीं दे सकता है।
- xlvii. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल पर विचार करने के संबंध में सेस्टेट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि वैश्विक प्रतिफल कम थे। इस निर्णय के बाद, सेस्टेट ने कई निर्णयों में 22% प्रतिफल को उचित ठहराया है।
- xlviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, यूरोपीय संघ और भारतीय प्राधिकारी द्वारा उचित बिक्री कीमत के निर्धारण में अंतर है। यूरोपीय संघ कच्चे माल, उपयोगिताओं और क्षमताओं के अनुकूलन और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सभी खर्चों के समायोजन के बिना कुल उत्पादन लागत के आधार पर उचित बिक्री कीमत निर्धारित करता है। इसलिए, यूरोपीय संघ द्वारा विचारित उचित बिक्री कीमत, लागत की पूरी वसूली के साथ-साथ कुछ लाभ भी प्रदान करता है।

### च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतिवादों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे दिया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों पर आधारित है।
53. इस अनुरोध के संबंध में कि 2020-21 को आधार वर्ष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इस अवधि के दौरान कीमतें असामान्य रूप से अधिक थीं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल आधार वर्ष की तुलना पर आधारित नहीं है।
54. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य 2020-21, 2021-22 और 2022-23 सहित क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक रहा है, तथापि जाँच अवधि में यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से एक बिंदु तक कम हो गया है। उक्त पहुँच मूल्य को अमेरिकी उत्पादक के बंद होने के बाद बाजार के सामान्य होने के कारण नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा दायर उत्तरों के अनुसार, उक्त उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद की पाटन कर रहे हैं। इस प्रकार, किसी भी स्थिति में, ऐसी कीमतों को भारतीय बाजार में उचित नहीं माना जा सकता है।
55. इस अनुरोध के संबंध में कि कोविड-19 के बाद आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण जाँच अवधि में कीमतें सामान्य हो गईं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक सहित संबद्ध वस्तुओं के केवल तीन उत्पादक हैं। तीनों उत्पादक लंबे समय से परिचालन में हैं और कोविड-19 के बाद किसी भी नए उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू नहीं किया है। इस प्रकार, यह अनुरोध कि आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण कीमतों में गिरावट आई, गलत है।
56. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति विश्लेषण के लिए ब्लैक रोज़ की कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए, न कि निर्यातक की कीमतों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकारी भारत में आयात मूल्य और उस मूल्य पर विचार करते हैं जिस पर घरेलू उद्योग आयातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि ब्लैक रोज़ जापान में उत्पादक के लिए एक अनन्य व्यापारी है, जबकि घरेलू उद्योग वास्तव में जापान के उत्पादक और निर्यातकों के आयात मूल्य के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पाटन के अभाव में, भारत में आयातक घरेलू उद्योग से स्रोत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे।
57. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह है क्योंकि स्थापित क्षमता अपरिवर्तित रही है जबकि नियोजित पूंजी, शुद्ध अचल संपत्तियां और मूल्यहास में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।
58. भारत में मांग-आपूर्ति अंतर होने संबंधी निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर भारत में पाटन का औचित्य नहीं है। वर्तमान जाँच भारत में संबद्ध वस्तुओं की पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी। यद्यपि मांग-आपूर्ति अंतर है, पाटन एक अनुचित व्यापार व्यवहार है जिसके कारण भारत में एकमात्र उत्पादक को वास्तविक क्षति हो रही है। विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से पता चलता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

59. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लाभप्रदता का सत्यापन करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पाटन और ऐसी पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में शुरू की गई है। चूँकि प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच की है, इसलिए डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लाभप्रदता की जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि आवेदक को उस समय डाउनस्ट्रीम उत्पाद से लाभ हुआ जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अधिक थीं।

### च.3.1. क्षति का संचयी मूल्यांकन

60. विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुच्छेद 3.3 और नियमों के अनुबंध II के पैरा (iii) में प्रावधान है कि यदि किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जाँच के अधीन है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:
- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के सात प्रतिशत से अधिक है, और
  - ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।
61. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में परस्पर तुलनीय गुण हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए और समान ग्राहक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
62. इस अनुरोध के संबंध में कि एक संबद्ध देश से आयात मूल्य दूसरे संबद्ध देश की तुलना में अधिक था और एक देश से आयात में वृद्धि हुई है जबकि दूसरे से आयात में कमी आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के संचयी मूल्यांकन के लिए इसका आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी जाँचों में, जहाँ एक से अधिक देशों से आयात का एक साथ आकलन किया जा रहा है, एक देश से आयात मूल्य हमेशा दूसरे देश से अधिक होगा।
63. इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जाँच में क्षति का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा।
- क. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है।
  - ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
  - ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश से आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

### च.3.2. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

#### क) मांग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

64. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
<b>खपत रहित</b>					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	110	151
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	4,199	4,951	5,013	4,211
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	11	3	21	-
कुल मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	118	107
<b>खपत सहित</b>					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	115	140
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	4,199	4,951	5,013	4,211
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	11	3	21	-
कुल मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	118	111

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग, जिसमें कैप्टिव खपत के साथ-साथ कैप्टिव खपत को छोड़कर, वर्ष 2022-23 तक वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है। जाँच अवधि में मांग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तथापि, आधार वर्ष की मांग की तुलना में जाँच अवधि में कैप्टिव खपत सहित और उसे छोड़कर मांग उच्च बनी रही है।

#### ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

66. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या आयात में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात मात्राएँ निम्नानुसार थीं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	4,199	4,951	5,013	4,211
चीन जन. गण. से आयात	मी.ट.	1,809	2,453	2,443	1,709
जापान से आयात	मी.ट.	2,390	2,498	2,571	2,502
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	11	3	21	-
कुल आयात	मी.ट.	4,210	4,954	5,034	4,211

संबद्ध आयात के संबंध में					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	107	82
खपत/मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	101	94
कुल आयात	%	99.7%	99.9%	99.6%	100%

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 और 2022-23 में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद जांच अवधि में इसमें गिरावट आई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा अधिक रही है।
- क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और खपत से संबंधित आयात में भी गिरावट आई है।
- जांच अवधि के दौरान भारत में हुए आयातों का संपूर्ण हिस्सा संबद्ध देशों से आयात है।

68. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद जापान से आयात में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान जापान से आयात में वृद्धि हुई है। किसी भी स्थिति में, चूंकि वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए अलग-अलग संबद्ध देशों से आयात की प्रवृत्ति की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

### च.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. संबद्ध देशों से आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित आयातों के कारण भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में मूल्य में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में कमी लाने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्यतः होती। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच मूल्य में कमी, कीमत हास और मूल्य हास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

### क) कीमत में कमी

70. कीमत में कमी विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है। इस संबंध में, समान व्यापार स्तर पर, उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री कीमत, सभी छूटों और करों को घटाकर, के बीच तुलना की गई है।

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	जापान	संबद्ध देश
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/मी.ट.	4,70,672	4,46,947	4,56,574
कीमत कटौती	₹/मी.ट.	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%



71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम हैं। सभी संबद्ध देशों से कीमतों में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

**ख) कीमत हास/न्यूनीकरण**

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, प्राधिकारी ने इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जाँच की है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	147	122
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	78	57
पहुँच कीमत	₹/मी.ट.	7,26,622	6,55,797	6,39,486	4,56,574
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	88	63

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान पहुँच मूल्य में भी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, जाँच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है, जबकि बिक्री कीमत में बिक्री लागत में गिरावट से अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों की पहुँच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और उन्हें कम कर दिया है।
74. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने कीमतें कम कर दी हैं जिससे निर्यातकों को कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में माँग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग के लिए कीमतें कम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। किसी भी स्थिति में, संबद्ध आयातों की पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत से म कीमतों पर बिक्री करने और वित्तीय घाटा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि को छोड़कर, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत के साथ-साथ संबद्ध आयातों के पहुँच कीमत में भी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत और संबद्ध आयातों के पहुँच मूल्य के बीच के अंतर में भी कमी आई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पहुँच कीमत	₹/मी.ट.	7,26,622	6,55,797	6,39,486	4,56,574
कच्ची सामग्री लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	125	69
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***

कच्ची सामग्री की लागत और पहुंच कीमत के बीच अंतर	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	57	41

### च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

76. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

#### क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

77. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	112	122
विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	112	122
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	110	151
निर्यात बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	73	86
आबद्ध खपत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	120	132

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी और उसके बाद घट गई। क्षति अवधि के दौरान निर्यात बिक्री में गिरावट आई है।

- घ. घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।
79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में उत्पादन में \*\*\*% की वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में \*\*\*% की वृद्धि हुई है। यह हितबद्ध पक्षकारों के इस कथन के विपरीत है कि घरेलू उद्योग एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मांग में आवेदक की कैप्टिव खपत और व्यापारिक मांग दोनों शामिल हैं। यदि आवेदक संबद्ध वस्तुओं की कैप्टिव खपत बंद कर देता है, तो उसे भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात करना होगा। ऐसे मामले में, आवेदक की कैप्टिव खपत वर्तमान जाँच के गुण-दोष में कोई परिवर्तन नहीं करती है।
80. यह भी देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में \*\*\*% की वृद्धि हुई, तथापि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में \*\*\*% की वृद्धि हुई।
81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि के कारण, जाँच अवधि के बाद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

#### ख) माँग में बाजार हिस्सा

82. आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	93	141
संबद्ध आयात	%	86%	86%	87%	80%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	101	94
अन्य आयात	%	0.2%	0.1%	0.4%	0.0%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	200	0

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में थोड़ी कम हुई और उसके बाद जाँच अवधि में वृद्धि हुई। आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है क्योंकि भारत में कम कीमत वाले आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग ने घाटे में बिक्री की है। इसके कारण, जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है और संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
84. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है क्योंकि उसने कीमतें कम करने के बावजूद बाजार हिस्सेदारी हासिल नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है क्योंकि इससे उसकी लाभप्रदता पर काफी समझौता हुआ है।

#### ग) मालसूची

85. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	160	313	249

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि भारत में पर्याप्त माँग है, फिर भी घरेलू उद्योग को भंडार के संचय के कारण नुकसान हुआ है।

**घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और विनियोजित पूँजी पर आय**

87. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और विनियोजित पूँजी पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	147	122
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	78	57
लाभ / (हानि)	₹/मी.ट.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	10	(6)
लाभ / (हानि)	₹ लाख	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	11	(9)
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	17	0.89
नियोजित पूँजी पर आय	%	***	***	***	(***)

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	7	(6)
-----------	----------	-----	----	---	-----

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग पिछले वर्षों के दौरान लाभ अर्जित कर रहा था, परंतु जांच अवधि के दौरान उसे वित्तीय घाटा हुआ है।
- नकद लाभ में भी यही प्रवृत्ति रही है और पूरी क्षति अवधि के दौरान इसमें साल-दर-साल गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ जांच अवधि के दौरान सबसे कम रहा।
- घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी पूरी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

89. इस अनुरोध के संबंध में कि नियोजित पूंजी पर आय में केवल निवल अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ है। पिछली किसी भी अवधि के लिए निवल अचल परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक है। इस प्रकार, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट निवल अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण नहीं है।

90. इस तर्क के संबंध में कि मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का ईबीडीआईटीए, जिसमें मूल्यहास शामिल नहीं है, भी क्षति अवधि के दौरान कम हुआ है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि के बाद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
ईबीडीआईटीए	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	15	1

### ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

91. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	95	94
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	112	122
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	118	130
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	120

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता के साथ-साथ वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

**च) वृद्धि**

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	-	-	-
उत्पादन	%	-	23	(9)	9
घरेलू बिक्री	%	-	18	(7)	38
प्रति इकाई लाभ / (हानि)	%	-	(55)	(78)	(162)
नकद लाभ	%	-	(52)	(68)	(96)
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	(58)	(83)	(188)

93. प्राधिकारी नोट करते हैं:

- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों ने 2021-22 में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, लेकिन 2022-23 में इसमें गिरावट आई। मात्रा मापदंडों ने जाँच अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मात्रा मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता से समझौता किया है।
- ग. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों ने पूरी क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

**छ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

94. चूँकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत के साथ-साथ बिक्री लागत से भी कम है, इसलिए इसने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। इसके अलावा, आयातों की

कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। इसके कारण, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित नहीं कर पाया है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

#### ज) पाटन की मात्रा

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

#### झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा। ऐसे में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान कीमतें किसी भी नए निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

#### ज) क्षति मार्जिन की मात्रा

97. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया है। जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आँकड़ों को अपनाकर संबद्ध वस्तुओं का क्षति-रहित कीमत निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से प्राप्त मूल्य की तुलना हेतु क्षति-रहित मूल्य पर विचार किया गया है। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। नियमों के अनुबंध III में निर्धारित अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियाँ और औसत कार्यशील पूंजी) पर कर-पूर्व लाभ के रूप में एक उचित प्रतिफल (22% की दर से कर-पूर्व) दिया गया है, जिससे क्षति-रहित मूल्य प्राप्त किया जा सके और उसका पालन किया जा रहा है।
98. सहकारी निर्यातकों के लिए प्राप्त मूल्य का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राप्त मूल्य का निर्धारण किया है।
99. इस तर्क के संबंध में कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अनुचित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी की यह एक सतत प्रथा रही है कि वे घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत का निर्धारण नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल के आधार पर करते हैं, जो 22% है, सिवाय तब जब रिकॉर्ड में इस बात के साक्ष्य हों कि 22% नहीं है और अधिक उपयुक्तता के लिए किसी अन्य पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए 22% से कम का प्रतिफल उपयुक्त होगा। ब्रिजस्टोन मामले में माननीय सीईएसटीएटी की टिप्पणियाँ कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण करने में 22% आरओसीई के उपयोग के संबंध में थीं, न कि क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की गणना में इसकी उपयुक्तता के संबंध में। इसके अतिरिक्त, ब्रिजस्टोन का निर्णय, एडी नियमों के अनुबंध-III के लागू होने से पहले का है, जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस पर भरोसा

करना अनुचित हो जाता है। बाद के मेरिनो पैनेल प्रोडक्ट्स मामले में, सीईएसटीएटी ने नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल लागू करने की प्राधिकारी की प्रथा को बरकरार रखा।

100. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत को हाइड्रोपरऑक्सीडेशन प्रक्रिया की लागत को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अनुबंध III के अनुसार, घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर विचार किया जाना है।
101. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी	पहुँच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	%	रेंज (%)
क	चीन जन.गण.					
1	झेजियांग होंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***%	15-25
2	अन्य	***	***	***	***%	30-40
ख	जापान					
3	सुमितोमो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***%	15-25
4	अन्य	***	***	***	***%	35-45

### च.3.5. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

102. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के क्षति, मात्रा और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति, नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है:

#### क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

103. यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि के दौरान भारत में किए गए आयातों में संबद्ध आयात शामिल हैं। इसलिए, यह क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं है।

#### ख. माँग में संकुचन

104. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग में गिरावट आई है। हालाँकि, भारत में माँग घरेलू उद्योग की क्षमताओं से कहीं अधिक है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति माँग में संकुचन के कारण नहीं है।

#### ग. खपत की पद्धति

105. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

#### घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ



106. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

#### ड. प्रौद्योगिकी में विकास

107. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

108. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति घरेलू उद्योग की अकुशल उत्पादन प्रक्रिया के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया घरेलू उद्योग की एक अंतर्निहित विशेषता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में निहित कारकों, जो इस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं, के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष कोई क्षति नहीं हुई है, भले ही वह जाँच अवधि के समान ही प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया के साथ काम कर रहा था। इस प्रकार, क्षति घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषता के कारण नहीं है।

#### च. उत्पादकता

109. क्षति अवधि के दौरान कैप्टिव उपभोग हेतु उत्पादन सहित घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन बढ़ा है। अतः, उत्पादकता में गिरावट के कारण क्षति नहीं हो सकती।

#### छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

110. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

#### ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

111. हुई क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में ही सूचना को पृथक किया है और प्रदान किया है।

#### झ. वैश्विक स्तर पर अन्य उत्पादकों का बंद होना और कोविड-19

112. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति कोविड-19 और कोविड-19 के बाद आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वैश्विक स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के केवल तीन उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में मांग भारतीय उद्योग की क्षमता से अधिक है। इस प्रकार, न तो आपूर्तिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और न ही बाजार में अधिक आपूर्ति है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

113. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि अमेरिका स्थित उत्पादक ने 2017 में अपना उत्पादन बंद कर दिया था। ऐसे उत्पादन बंद होने का कोई भी प्रभाव अतीत में प्रासंगिक रहा होगा। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग पर ऐसे उत्पादन बंद होने के प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

#### ट. रूस-यूक्रेन संकट के कारण कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत

114. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि रूस-यूक्रेन संकट के कारण कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि रूस-यूक्रेन संकट के कारण घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। किसी भी स्थिति में, ऐसा प्रभाव वैश्विक स्तर पर सभी उत्पादकों पर लागू होता है, न कि केवल घरेलू उद्योग पर।

115. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सामान्य व्यावसायिक परिदृश्य में, संबद्ध वस्तुओं के बिक्री कीमत में कच्चे माल की कीमत के अनुसार उतार-चढ़ाव होना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं देखा गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में गिरावट आई है। इस प्रकार, कच्चे माल की कीमत के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

### छ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

#### छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक का प्रभाव विश्लेषण केवल टायर उद्योग पर केंद्रित है, और रंग, दवा और कृषि रसायन जैसे अन्य प्रभावित क्षेत्रों की उपेक्षा करता है। रेसोर्सिनाॅल की बढ़ी हुई लागत कई उद्योगों में कीमतों में वृद्धि करेगी, मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करेगी।
- ii. घरेलू उद्योग ने तत्काल डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के बजाय टायर उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गलत गणना की है।
- iii. घरेलू उद्योग ने एसआईओएन मानदंडों के आधार पर शुल्कों के प्रभाव की गणना की है, लेकिन केवल टायर में रेसोर्सिनाॅल की खपत पर विचार किया है, जबकि रेजिन और कपड़े की खपत को अनदेखा किया है, जो क्रमशः रेसोर्सिनाॅल का उपयोग करके और उसमें डुबोकर उत्पादित किए जाते हैं।
- iv. शुल्क लगाने से संबंधित वस्तुओं की लागत में 10-15% की वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लाभ में 90-100% की कमी आएगी।
- v. शुल्क लगाने से अतुल को घरेलू बाजार पर अपना दबदबा बनाने का मौका मिल जाएगा, जिससे डाउनस्ट्रीम उत्पादों में प्रतिस्पर्धियों को नुकसान होगा। अतुल द्वारा कुछ खरीदारों को आपूर्ति करने से इनकार करना और निर्यात को प्राथमिकता देना, निरंतर आयात की आवश्यकता को और भी पुष्ट करता है।
- vi. 2017 में आईएनडीएसपीईसी संयंत्र के बंद होने के साथ, दुनिया में केवल तीन रेसोर्सिनाॅल निर्माता (चीन, जापान और भारत) बचे हैं, इसलिए, संबंधित आयातों द्वारा अन्य देशों से आयात को कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
- vii. अतुल में घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता का अभाव है और यह एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत, आयातक विश्वसनीयता प्रदान करते हैं, जिससे सुचारू औद्योगिक संचालन सुनिश्चित होता है। पाटनरोधी शुल्क से कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति में व्यवधान और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं में विश्वास में कमी आएगी।
- viii. 2017 में वैश्विक रेसोर्सिनाॅल की कमी के दौरान, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें बढ़ा दीं और उपयोगकर्ताओं को मात्रा में आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। जापानी उत्पादक ने उक्त अवधि में भारतीय उपयोगकर्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की। पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग वैश्विक बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- ix. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद, आवेदक ने भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक उपाय मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करना होगा। मौखिक सुनवाई के दौरान, जबकि आवेदक ने अनुरोध किया कि वह क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है, कोई ठोस विवरण साझा

नहीं किया गया है। क्षमता विस्तार के अभाव में, उपयोगकर्ताओं के हित में वर्तमान मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- x. आयातित रेसोर्सिनाॅल की तुलना में भारतीय रेसोर्सिनाॅल डाई संश्लेषण में अलग तरह से व्यवहार करता है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
- xi. घरेलू उद्योग पुरानी सल्फोनेशन संलयन प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
- xii. अपने उपयोगकर्ता लाभप्रदता विश्लेषण में, घरेलू उद्योग ने टेक्नो वैक्सकेम से संबंधित आंकड़ों को गलती से 'करोड़ों' में दर्शाया, जबकि वे 'लाखों' में थे।

## छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

117. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. जनहित का निर्धारण (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, और (घ) आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा परिमाणित प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख उपभोक्ता वर्ग पर है। जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य वर्गों में अधिक प्रभाव का दावा किया है, ऐसे वर्गों के उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है।
- iii. तत्काल डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि को अपने डाउनस्ट्रीम उद्योग पर डाल देता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अतीत में विचाराधीन उत्पाद की उच्च कीमतों के कारण टेक्नो वैक्सकेम की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार, प्रभाव की गणना उस उद्योग पर की गई है जो पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव वहन करता है।
- iv. चूँकि यह उत्पाद खुदरा स्तर पर नहीं बेचा जाता है और टायर उद्योग की कीमतों में रेसोर्सिनाॅल की कीमत में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- v. डाउनस्ट्रीम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि के संबंध में प्रभाव का परिमाणन किया गया है। अन्य सभी मानदंड समान स्तर पर रखे गए हैं।
- vi. चूँकि रेसोर्सिनाॅल एक कमोडिटी उत्पाद है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। उपभोक्ता प्रस्तावित कीमतों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को बदलने में सक्षम हैं।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए आवेदक को अनुचित लाभ नहीं होगा क्योंकि यह संबद्ध वस्तुओं को बाजार संचालित कीमतों पर डाउनस्ट्रीम उत्पादन के लिए स्थानांतरित करता है।
- viii. आवेदक ने केवल उन्हीं मामलों में आपूर्ति से इनकार किया है जहाँ उपभोक्ताओं ने अनुचित रूप से कम कीमतों की मांग की थी। उपभोक्ताओं ने आवेदक से मूल्य उद्धरण लिए हैं और निर्यातकों के साथ कीमतों पर बातचीत की है।
- ix. अमेरिकी उत्पादक के बंद होने के बाद, उपभोक्ताओं ने अतुल से संपर्क किया क्योंकि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की कमी थी। हालाँकि आवेदक उस समय आपूर्ति करने में

- असमर्थ था क्योंकि वह नियमित ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा था, यह देश में घरेलू उत्पादन के महत्व को दर्शाता है।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, अमेरिकी उत्पादक के बंद होने के बाद कीमतों में वृद्धि बाजार में मांग-आपूर्ति की शक्तियों के कारण हुई थी। संबद्ध वस्तुओं की कीमत न केवल घरेलू उत्पादक के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर उत्पादकों के लिए भी बढ़ी और यहाँ तक कि चीन और जापान के उत्पादकों ने भी कीमतें बढ़ा दीं। यदि पाटन पर लगाम नहीं लगाई गई और घरेलू उद्योग को उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर किया गया तो ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है।
  - xi. आवेदक ने पिछली जाँच अवधि की तुलना में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। आवेदक ने आगे भी क्षमताओं के विस्तार की योजना बनाई है।
  - xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, भले ही घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार की योजना नहीं बनाई हो, फिर भी यह घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपाय प्राप्त करने से नहीं रोकता है।
  - xiii. चीन अपने घरेलू बाजारों में उचित बाजार स्थितियाँ बनाए रखता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने जापान से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अतिरिक्त, अतीत में, चीन द्वारा अमेरिका से आयात पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
  - xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, माँग-आपूर्ति का अंतर शुल्क न लगाने का कारण नहीं हो सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। प्राधिकारी ने पिछले कई मामलों में, जहाँ माँग-आपूर्ति का अंतर था, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
  - xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग अप्रतिस्पर्धी नहीं बनेगा क्योंकि केवल भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग को ही अन्य देशों के डाउनस्ट्रीम उद्योग की तुलना में कम कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध है। इसके अलावा, निर्यात के उद्देश्य से, डाउनस्ट्रीम उद्योग पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना अग्रिम प्राधिकारी के तहत उत्पाद का आयात कर सकता है।
  - xvi. इस दलील के विपरीत कि घरेलू उत्पाद डाई संश्लेषण के लिए अलग तरह से व्यवहार करता है, घरेलू उद्योग डाई संश्लेषण खंड में ग्राहकों को आपूर्ति करता रहा है।
  - xvii. यह उत्पाद अत्यधिक पूंजी गहन है और बाजार की स्थिति किसी भी नए निवेश के लिए अनुकूल नहीं है।
  - xviii. घरेलू उद्योग की दलीलों के विपरीत, चूँकि वैश्विक स्तर पर केवल 3 निर्माता हैं, इसलिए घरेलू उद्योग के लिए अपनी व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए भारत में उचित बाजार मूल्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
  - xix. छोटे पैमाने के उपयोगकर्ता घरेलू उद्योग से कम मात्रा में खरीद करने में सक्षम हैं। हालाँकि, वे इतनी कम मात्रा में सीधे आयात नहीं कर पाएंगे और व्यापारियों को अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर होंगे।
  - xx. चीनी और जापानी उत्पादकों की संयुक्त क्षमता उनके देश में घरेलू मांग से अधिक है। भारत एक आकर्षक बाजार है जिसके कारण संबद्ध देशों के उत्पादकों ने भारत को निर्यात के लिए कीमतें कम कर दी हैं।

- xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलीलों के विपरीत, आवेदक के संयंत्र को भारत में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हानिकारक नहीं पाया गया है।
- xxii. चूंकि विचाराधीन उत्पाद टायर उद्योग का एक नगण्य हिस्सा है, इसलिए टायर निर्माताओं के साथ-साथ टायर कॉर्ड फैब्रिक निर्माताओं ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- xxiii. टेक्नो वैक्सकेम अन्य देशों की तुलना में बहुत कम कीमतों पर चीन को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करता है। या तो एक प्रतिपूरक समझौता है या उत्पाद में उच्च मार्जिन शामिल है जो टेक्नो वैक्सकेम को कम कीमत वसूलने की अनुमति देता है।
- xxiv. कम कीमतों पर आयात के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच की अवधि के बाद मात्रा के साथ-साथ मूल्य मानदंड और भी खराब हो गए हैं।
- xxv. आवेदक आत्मनिर्भर भारत और कच्चे माल की घरेलू खरीद को बढ़ावा देता है।

### छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है, बल्कि यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार अक्षुण्ण रहेगा। पाटनरोधी उपायों का लागू होना पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित करने से रोकने का काम करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं में बाधा नहीं, बल्कि सहायक हैं।
- 119. प्राधिकारी ने आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए, जांच आरंभ अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है।
- 120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक कमोडिटी उत्पाद है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का पहुँच मूल्य और बिक्री कीमत एक साथ चलते हैं। चूंकि यह एक कमोडिटी उत्पाद है, इसलिए उपयोगकर्ता आसानी से आपूर्तिकर्ता बदल सकते हैं और अनुमोदन की कोई लंबी आवश्यकता नहीं है।
- 121. वैश्विक स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के केवल तीन उत्पादक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि यद्यपि घरेलू उद्योग में भारत में कुल मांग के [\*\*\*]% को पूरा करने की क्षमता है, फिर भी जांच अवधि के दौरान इसका बाजार \*\*\*% से नीचे रहा है। डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए आपूर्ति के कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता बनाए रखना आवश्यक है।
- 122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर है और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में और निवेश की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु संयंत्र अत्यधिक पूंजी गहन है। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, एक उत्पादक को ब्राउन फील्ड निवेश हेतु [\*\*\*] मीट्रिक टन क्षमता हेतु ₹ [\*\*\*] करोड़ का निवेश

- करना आवश्यक है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक है और इसलिए, किसी भी नए संयंत्र के लिए निवेश व्यवहार्य नहीं है।
123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए क्षमता विस्तार की योजनाएँ साझा की हैं। हालाँकि, वर्तमान बाजार स्थिति के कारण ऐसे निवेश संभव नहीं हैं। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा हुआ है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में, आवेदक या किसी अन्य उत्पादक द्वारा भारत में निवेश करने की संभावना नहीं है।
124. भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर के निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति का अंतर भारत में पाटन का औचित्य नहीं है। प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने से नहीं रोकता है।
125. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उद्योग को उत्पाद की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आपूर्ति करने से इनकार अमेरिकी उत्पादक के बंद होने के समय वैश्विक स्तर पर सामग्री की अत्यधिक कमी के कारण था, हालाँकि, उस समय भी, घरेलू उद्योग ने नियमित ग्राहकों को आपूर्ति करने से इनकार नहीं किया था। घरेलू उद्योग ने आगे कहा है कि ये अनुरोध उन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए हैं जो हमेशा उत्पाद के आयात पर निर्भर रहे हैं और केवल कमी की अवधि के दौरान ही घरेलू उद्योग से संपर्क करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि ये उचित मूल्य पर उपलब्ध हों।
126. आवेदक द्वारा कैप्टिव उपभोग और निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी ने पहले ही नोट कर लिया है कि मांग-आपूर्ति का अंतर प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने से नहीं रोकता है।
127. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत बढ़ जाएगी और यह अव्यवहार्य हो जाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग की व्यवहार्यता विचाराधीन उत्पाद की पाटित कीमतों पर निर्भर नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए तत्काल डाउनस्ट्रीम उद्योग पास-थ्रू प्रकृति का है। विचाराधीन उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के साथ डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमतें भी बदलती रहती हैं।
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन ने अपने बाजार में उचित मूल्य बनाए रखने के लिए जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इस प्रकार, चीन में विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
129. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उसे अनुचित लाभ होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक को उस समय लाभ हुआ जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अधिक थीं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद को बाजार संचालित कीमतों पर डाउनस्ट्रीम उद्योग को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार, डाउनस्ट्रीम उत्पाद में आवेदक को कोई अनुचित लाभ नहीं होगा।

130. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वर्तमान में भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग को पाटित कीमतों पर उपलब्ध है। वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के केवल तीन विनिर्माता हैं। चूँकि चीन जनवादी गणराज्य और जापान में विचाराधीन उत्पाद की कीमत भारत में विचाराधीन उत्पाद की कीमत से अधिक है, इसलिए भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग अन्य देशों के डाउनस्ट्रीम उद्योग की तुलना में अप्रतिस्पर्धी नहीं बनेगा। निर्यात बाजार में डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रदर्शन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्यात हेतु, उपयोगकर्ता उद्योग, पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना, अग्रिम लाइसेंस के तहत विचाराधीन उत्पाद का आयात कर सकता है।
131. इस अनुरोध के संबंध में कि भारतीय रेसोर्सिनाॅल डाई संश्लेषण के लिए अलग तरह से व्यवहार करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग डाई संश्लेषण खंड को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करता रहा है। चूँकि उपयोगकर्ताओं ने घरेलू उद्योग से नियमित रूप से संबद्ध वस्तुओं की खरीद की है, इसलिए उक्त खंड के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद की स्वीकार्यता पर कोई संदेह नहीं है।

## ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

### ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जारी किए गए प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. याचिका में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु दावा किए गए समायोजनों के साक्ष्य शामिल नहीं हैं और आवेदक ने इस संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
  - ii. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में दिए गए जापान से आयातों और आवेदन में आवेदक द्वारा दिए गए अंतर का कारण नहीं बताया है।
  - iii. एससीसी देश में एकमात्र उत्पादक होने के कारण जापान में कीमतें अधिक हैं। एससीसी घरेलू बाजार में प्रीमियम वसूलने में सक्षम है क्योंकि यह जापान में एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।
  - iv. पूरी क्षति अवधि के लिए कीमत कटौती का आकलन किया जाना चाहिए।
  - v. भारतीय बाजार में कीमतों में गिरावट बाजार के सामान्य होने के कारण है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में भी गिरावट आई है।
  - vi. 2021-22 के दौरान लंबे समय तक बंद रहने और चीन में अपेक्षाकृत कम मांग के कारण वैश्विक बाजार में चीन से अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता थे। इससे वैश्विक बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति हुई जिससे रेसोर्सिनाॅल की कीमत सामान्य हो गई।
  - vii. आवेदक और चीन के उत्पादक के बीच कीमत युद्ध के कारण एससीसी को भारतीय बाजार में कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जापान से आयात कीमत 2022-23 तक स्थिर रही, लेकिन इस अवधि में भी घरेलू उद्योग की पहुँच कीमत और बिक्री कीमत में गिरावट आई।
  - viii. आवेदक की मालसूची में वृद्धि बाजार की गतिशीलता की अनदेखी करने और उसके एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता होने के कारण हुई है।

- ix. आवेदक अपनी कीमतें संबद्ध आयातों की कीमतों से ऊपर रखने के बावजूद अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहा है। इस प्रकार, आयात की कीमत के कारण आवेदक की बाजार हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होती है।
- x. प्राधिकारी ने आवेदक के एनएफए और मूल्यहास में बेतुके उतार-चढ़ाव का कोई कारण नहीं बताया है।
- xi. यद्यपि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों पर भरोसा किया है, तथापि, जांच की बाद की अवधि के लिए पहुँच कीमत और पाटन की जांच नहीं की गई है।
- xii. प्राधिकारी ने अकुशल प्रौद्योगिकी के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का विश्लेषण नहीं किया है। घरेलू उद्योग को क्षति केवल उपयोग की गई उत्पादन प्रौद्योगिकी के कारण हुई है।
- xiii. घरेलू उद्योग को क्षति मांग में गिरावट के कारण हुई है। यद्यपि आवेदक को मात्रा संबंधी क्षति नहीं हुई होगी क्योंकि मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है, फिर भी उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं।
- xiv. यद्यपि प्राधिकारी ने नोट किया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि वैश्विक स्तर पर सभी उत्पादकों को प्रभावित करेगी, लेकिन इस वृद्धि का एससीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह निजी तौर पर बेंजीन का उत्पादन करता है। हालाँकि, आवेदक बेंजीन खरीदता है।
- xv. जब पाटनरोधी शुल्क लागू था और बाजार में आपूर्ति की कमी थी, तब आवेदक ने व्यापारिक बाजार में संबद्ध वस्तुओं की अधिक मात्रा में आपूर्ति नहीं की। आवेदक का ध्यान निजी उपभोग और निर्यात बाजार पर केंद्रित रहा।
- xvi. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत उसकी अकुशल उत्पादन प्रक्रिया के कारण अधिक है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग को अनावश्यक रूप से दंडित किया जाएगा।
- xvii. चूँकि वैश्विक स्तर पर उत्पादकों की संख्या सीमित है, इसलिए बाजार पर कड़ा नियंत्रण है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से भारत में प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xviii. 20% पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत 13-18% बढ़ जाएगी।
- xix. बेंचमार्क शुल्क पूर्व में प्रभावी थे, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इनकी न तो समीक्षा की गई और न ही इसका समय विस्तार किया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी।
- xx. आयातकों का अनुरोध है कि मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाना चाहिए। चूँकि संबद्ध वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए स्थिर या संदर्भ मूल्य शुल्क लगाना प्रयोक्ताओं के लिए दंडात्मक होगा।
- xxi. रेसो-टार संबद्ध वस्तुओं का एक उप-उत्पाद है और कुछ रेजिन के उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष 1:1 विकल्प के रूप में कार्य करता है। आवेदक इसका उपयोग निजी रूप से करता है और इसे व्यापारिक बाजार में नहीं बेचता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की लागत की जाँच कर सकते हैं और यह भी देखें कि क्या ऐसी लागत की वसूली पर विचार किया गया है।

## ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध



133. घरेलू उद्योग ने जारी किए गए प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- xxii. उपयोगिता की प्रति इकाई लागत निकालने, निर्यात प्रोत्साहन का उपचार और विचाराधीन उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की गणना करने की पद्धति के संदर्भ में घरेलू उद्योग के दावे के साथ तुलना करते समय क्षतिरहित कीमत की गणना में त्रुटि प्रतीत होती है।
- xxiii. आवेदक ने संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा किए गए बीजक-पश्चात छूट और प्रतिपूरक करारों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। आवेदक अनुरोध करता है कि उस पर विचार किया जाना चाहिए।
- xxiv. आवेदक ने क्षति अवधि से पहले क्षमताओं का विस्तार किया है और आगे क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है। हालाँकि, संबद्ध वस्तुएँ पूंजी गहन प्रकृति की हैं, और वर्तमान बाजार स्थिति किसी भी आगे के निवेश के लिए अनुकूल नहीं है।
- xxv. भारत में अपने उत्पाद के लिए बाजार की कमी के कारण घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घाटे में बेचने और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के बाद भी, घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

### ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 134. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोधों की जाँच की है और नोट करते हैं कि कई अनुरोध पुनरावृत्तियाँ हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जाँच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और साक्ष्य सहित समर्थित मुद्दों को प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है और उसकी जांच निम्नानुसार की गई है।
- 135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक ने निर्यात कीमत में समायोजन के साक्ष्य का प्रकटन नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। इसके अलावा, निर्यात कीमत के लिए किए गए समायोजनों का उल्लेख प्रकटन विवरण में किया गया था।
- 136. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात मात्रा और प्राधिकारी द्वारा विचारित आयात मात्रा के बीच असमानता का कारण नहीं बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहाँ आवेदक ने आयात मात्रा का आकलन करने के लिए अपनी बाजार आसूचना पर भरोसा किया है, वहीं प्राधिकारी ने जारी किए गए प्रकटन विवरण में डीजी प्रणाली के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- 137. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि जापान में कीमतें एससीसी के देश में एकमात्र उत्पादक और आपूर्तिकर्ता होने के कारण अधिक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक द्वारा इसका कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया कि घरेलू बाजार में कीमतें अत्यधिक अधिक हैं। केवल इस तथ्य को कि कोई उत्पादक देश में एकमात्र उत्पादक है, कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में उत्पाद का आयात हमेशा देश में किया जा सकता है। इसलिए, यह तथ्य कि बाजार में एकमात्र उत्पादक मौजूद है, प्रतिस्पर्धा के अभाव का संकेत नहीं देता। इसे देखते हुए, प्राधिकारी इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों में कोई दम नहीं पाते।

138. इस निवेदन के संबंध में कि समग्र क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती का निर्धारण नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्य कटौती का निर्धारण केवल जाँच अवधि के लिए किया जाता है क्योंकि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति का निर्धारण जाँच अवधि के संदर्भ में किया जाता है, और क्षति की प्रवृत्ति का निर्धारण क्षति अवधि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने समग्र क्षति अवधि के लिए मूल्य दमन और अवमंदन की जाँच की है।
139. इन अनुरोधों के संबंध में कि बाजार का सामान्यीकरण इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. और जापान में कीमतें भारत की तुलना में अधिक हैं, जो संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में, भले ही वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट आई हो, भारतीय बाजार में स्पष्ट पाटन है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात अपनी बिक्री लागत से अधिक कीमतों पर किया है, जबकि उसने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बेचा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अभी भी निर्यात बाजार में लाभ कमा रहा है। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग को क्षति भारत में पाटन के कारण हुई है, न कि बाजार के सामान्य होने के कारण।
140. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2021-22 में चीन जन.गण. में शटडाउन और मांग में गिरावट के कारण अतिरिक्त आपूर्ति हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में मांग में गिरावट का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि 2021-22 में मांग में गिरावट आई भी, तो जांच की अवधि में ऐसी गिरावट का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे भारत में कीमतों में गिरावट आई हो। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से यह स्पष्ट है कि ऐसे उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं। इस प्रकार, भारतीय बाजार में कीमतों में गिरावट पाटन के कारण हुई है।
141. जहां तक इन अनुरोधों का संबंध है घरेलू उद्योग और चीन के उत्पादकों के बीच कीमत युद्ध के कारण एससीसी को कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से पहुंच कीमत चीन की पहुंच कीमत से कम है। ऐसे मामले में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एससीसी की ओर से कीमत में गिरावट अन्य उत्पादकों की ओर से कीमतों में गिरावट के कारण है। किसी भी स्थिति में, जापान का उत्पादक भारतीय बाजार में पाटन कर रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त उत्पादक द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के आधार पर पाटन मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।
142. इन अनुरोधों के संबंध में कि संबद्ध देशों के उत्पादक बीजक-प्रक्रिया के बाद छूट प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने प्रतिपूरक करार किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया गया है। प्राधिकारी ने सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।
143. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहा है, भले ही इसकी बिक्री कीमत आयात कीमत से अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के दौरान घाटे में बिक्री की है। घाटे में बिक्री के कारण, घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने घाटे में बिक्री की है, फिर भी क्षति अवधि के दौरान उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है।

144. जहाँ तक इन अनुरोधों का संबंध है कि घरेलू उद्योग की सूची में बाजार की गतिशीलता की अनदेखी करने और एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता होने के कारण वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के लिए अपनी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने हेतु बाजार में पर्याप्त मांग है। तथापि, यद्यपि उसने अपनी कुल क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है, फिर भी मालसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने घाटे में बिक्री की है, फिर भी उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है क्योंकि पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही थी। इससे पता चलता है कि भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ है।
145. जाँच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विश्वास करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। अतः, जाँच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है।
146. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लागत पुरानी उत्पादन प्रक्रिया के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसके द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया स्थिर, कुशल और अधिक पर्यावरण अनुकूल है। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया गया है कि सल्फोनेशन संलयन प्रक्रिया में पूंजीगत निवेश अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक की कच्चे माल की लागत एसआईओएन मानदंडों की तुलना में [\*\*\*] रु. प्रति किलोग्राम कम है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया अकार्यक्षम है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि संबंधित पैराओं में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग को किसी भी विगत वर्ष में क्षति नहीं हुई है, यद्यपि वह उसी उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग कर रहा था।
147. जहाँ तक इन अनुरोधों का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति माँग में कमी के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट भारत में पाटन के कारण हुई है। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रही हैं। चूँकि संबद्ध वस्तुएँ एक कमोडिटी उत्पाद हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अपनी बिक्री लागत से नीचे कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।
148. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत में गिरावट आई है। पहुँच कीमत और कच्चे माल की लागत के बीच अंतर कम हुआ है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण नहीं है।
149. मूल्यहास और एनएफए में वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने व्ययों के आवंटन और संविभाजन की कार्यप्रणाली का सत्यापन किया है और पाया है कि ये व्यय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के सिद्धांतों और सामान्य लागत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि संबंधित भाग में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग को हुई क्षति मूल्यहास में वृद्धि के कारण नहीं है क्योंकि पीबीडीआईटी, जिसमें मूल्यहास और ब्याज शामिल नहीं है, में भी गिरावट आई है।

150. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं हुई, जबकि बाजार में कमी थी और पाटनरोधी शुल्क लागू था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्डों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि उस समय घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। इस प्रकार, यदि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में सुधार नहीं भी होता है, तो भी वह पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद अपने उत्पाद को उचित कीमत पर बेच सकेगा।
151. इन अनुरोधों के संबंध में कि भारतीय बाजार में उत्पादकों की संख्या सीमित है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत बढ़ जाएगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग को अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की तुलना में बहुत कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं तक पहुँच प्राप्त है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि संबद्ध देशों के उत्पादक भारत में आयात की कीमतों से अधिक कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं को बेच रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर, पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की भरपाई हो जाएगी। चूँकि भारत में केवल एक ही उत्पादक है, इसलिए ऐसे उत्पादक की व्यवहार्यता बनाए रखना आवश्यक है।
152. इन अनुरोधों के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत में 15-18% की वृद्धि होगी, प्राधिकारी ने संबंधित खंड में पहले ही नोट कर लिया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पास-थ्रू प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्डों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की कीमत विगत में अपेक्षाकृत अधिक थी। तथापि, ऐसी अवधि के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई साक्ष्य नहीं है।
153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्डों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, आवेदक ने क्षति अवधि से पहले क्षमताओं का विस्तार किया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने क्षमताओं का और विस्तार करने के अपने इरादे को दर्शाने वाले साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु एक नया ब्राउनफील्ड संयंत्र स्थापित करने के लिए [ \*\*\* ] करोड़ रु. या [ \*\*\* ] लाख रु. प्रति मी. टन के निवेश की आवश्यकता है। चूँकि आवेदक को जाँच की अवधि के दौरान वित्तीय हानि के साथ-साथ नकद हानि भी हुई है, इसलिए वर्तमान बाजार स्थिति किसी और निवेश के लिए अनुकूल नहीं है।
154. उपयोगिता की प्रति इकाई लागत निकालने, निर्यात प्रोत्साहन के उपचार और विचाराधीन उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की गणना में कार्यप्रणाली के संदर्भ में घरेलू उद्योग के दावे के साथ तुलना करते समय क्षतिरहित की (एनआईपी) की गणना में त्रुटि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जाँच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत से संबंधित आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जिसका सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के सिद्धांतों को लागू करते हुए नमूना आधार पर विधिवत सत्यापन किया गया था। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता, कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी के निर्धारण की कार्यप्रणाली के संबंध में, बहु-उत्पाद कंपनी के मामले में विचाराधीन उत्पाद

के लिए कार्यशील पूंजी निर्धारित करने हेतु प्राधिकारी की सुसंगत कार्य-प्रणाली का इस मामले में पालन किया गया है।

155. पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप के संबंध में, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में मानक शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इस प्रकार के शुल्क से यह सुनिश्चित होगा कि भारत में उचित कीमत बहाल हों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई हो।
156. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी को उप-उत्पाद की वसूली का सत्यापन करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उप-उत्पाद का निजी उपभोग किया है। प्राधिकारी ने ऐसे उप-उत्पाद के लिए ऋण को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का निर्धारण किया है।

#### झ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

157. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
  - i. विचाराधीन उत्पाद रेसोर्सिनॉल है, जिसे बाजार की भाषा में 1,3-बेंजीनडायॉल; 1,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्जीन; 3-हाइड्रॉक्सीफेनॉल; रेसोर्सिन मेटा-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्जीन के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र सी6एच6O2 है।
  - ii. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन सुफोनेशन फ्यूजन प्रक्रिया, हाइड्रोपरऑक्सीडेशन प्रक्रिया या एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करके किया जा सकता है। तथापि, अंतिम उत्पाद की विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है, चाहे उनका उत्पादन सल्फोनेशन-फ्यूजन, हाइड्रोपरऑक्सीडेशन या एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किया गया हो।
  - iii. घरेलू उद्योग ने भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए अलग-अलग विनिर्माण प्रक्रियाएं होने के बावजूद, अंतिम उत्पाद का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।
  - iv. आवेदक ने अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. में अपनी संबंधित इकाई से विचाराधीन उत्पाद की नगण्य मात्रा का आयात किया था। चूंकि ऐसे आयात मात्रा में नगण्य थे और जाँच की अवधि से पहले किए गए थे, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे आयात वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक की घरेलू उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पात्रता में बाधा नहीं डालते हैं।
  - v. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और इस प्रकार, भारत में संपूर्ण घरेलू उत्पादन का उत्तरदायित्व उसी का है। नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग है।

- vi. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ डीजी प्रणाली के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- vii. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।
- viii. प्राधिकारी ने क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है क्योंकि वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।
- ix. भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:
  - (क) संबद्ध आयातों की मात्रा 2022-23 तक बढ़ी, लेकिन जाँच की अवधि में इसमें गिरावट आई। हालाँकि, जाँच अवधि में आयात की मात्रा आधार वर्ष में आयात की मात्रा से अधिक थी।
  - (ख) संबद्ध आयात भारत में होने वाले आयातों का संपूर्ण हिस्सा हैं।
  - (ग) सभी संबद्ध देशों से कीमतों में कटौती सकारात्मक और अधिक है।
  - (घ) संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का हास और न्यूनीकरण हुआ है। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण क्षति अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई है। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी।
  - (ङ) घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतों को अपनी बिक्री लागत से एक बिंदु नीचे तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
  - (च) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
  - (छ) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है।
  - (ज) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा और नकद घाटा हुआ है।
  - (झ) घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया है।
  - (.ज) संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं।
  - (ट) घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा हुआ है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया गया है।
- x. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।
- xi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारतीय बाजार में पाटन के कारण हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

- xii. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर कोविड-19 या अमेरिका में उत्पादक के बंद होने के प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं।

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को उचित अवसर मिलेगा।
- ख. विचाराधीन उत्पाद एक कमोडिटी उत्पाद है, जो प्रयोक्ताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्तिकर्ताओं को बदलने की अनुमति देता है।
- ग. घरेलू उद्योग में भारत में [50%] मांग को पूरा करने की क्षमता है, हालाँकि, इसका हिस्सा 20% से कम रहा है।
- घ. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर केवल तीन उत्पादकों द्वारा किया जाता है। आपूर्ति के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोतों की कमी को देखते हुए, घरेलू उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- ङ. मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है। किसी भी स्थिति में, आयात मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक है।
- च. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होगा।
- छ. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि से पहले ही क्षमताओं का विस्तार कर लिया है। घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार की आगे भी योजनाएँ हैं।
- ज. वर्तमान बाजार की स्थिति नए निवेश के लिए व्यवहार्य नहीं है। यदि स्थिति में सुधार नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिससे भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ जाएगा।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन बंद करने की स्थिति में, भारतीय आयातक पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएँगे क्योंकि देश में घरेलू आपूर्ति का कोई स्रोत नहीं होगा।
- ञ. डाउनस्ट्रीम उद्योग, डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकारी योजना के अंतर्गत, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर सकता है। इस प्रकार, प्रयोक्ता वैश्विक बाजार में अप्रतिस्पर्धी नहीं बनेंगे।

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

159. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कमतर हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की

सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए संदर्भ कीमत के बीच के अंतर के बराबर होगा, बशर्ते पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो।

**शुल्क तालिका**

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2907 21 00	रेसोर्सिनाॅल	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	झेजियांग हांगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	6244	एमटी	यूएसडा.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 में उल्लिखित देश के अलावा कोई अन्य देश	6244	एमटी	यूएसडा.
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और जापान के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	6244	एमटी	यूएसडा.



4.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड	6244	एमटी	यूएसडा.
5.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	क्र.सं. 4 में उल्लिखित देश के अलावा कोई अन्य देश	6244	एमटी	यूएसडा.
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और जापान के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई	6244	एमटी	यूएसडा.

160. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 और 9ए के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

**ज. आगे की प्रक्रिया**

161. इन अंतिम जांच परिणामों के कारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(DEPARTMENT OF COMMERCE)**  
**(Directorate General of Trade Remedies)**

**NOTIFICATION**

**FINAL FINDINGS**

**CASE NO. AD (OI) – 25/2024**

New Delhi, the 24<sup>th</sup> September, 2025

**Subject: Anti-dumping investigation into imports of “Resorcinol” originating in or exported from China PR and Japan.**

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

**F. No. 6/27/2024-DGTR:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules).

1. Whereas, Atul Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Resorcinol (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR and Japan (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/27/2024-DGTR dated 30<sup>th</sup> September 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from China PR and Japan in accordance with Rule 5 of the Anti- Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**A. PROCEDURE**

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

- b. The Authority issued a public notice dated 30<sup>th</sup> September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject countries.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the email addresses made available by the applicant and requested them to make their views in writing within the prescribed time limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
- e. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. Apeloa Pharmaceutical Co., Ltd
  - ii. Buipo International
  - iii. Changshan Haicheng Chemical Co Ltd
  - iv. East West Corporation
  - v. Farmasino Co Ltd
  - vi. Hangzhou Better Chemtech Ltd
  - vii. Hangzhou Verychem Science and Technology Co Ltd
  - viii. Kenko Corporation
  - ix. Shanghai Amino-Chem Co., Ltd
  - x. Sojitz Corporation
  - xi. Sumitomo Chemical Co. Ltd.
  - xii. Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd.
- f. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- g. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:

- i. Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd.
  - ii. Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.
  - iii. Zhejiang Dystar Trading Co., Ltd.
  - iv. Amino-Chem (HK) Co Limited
  - v. Sojitz Corporation
  - vi. Sumitomo Chemical Co. Ltd.
  - vii. B.R. Chemicals
  - viii. Songwon International – Japan K.K.
  - ix. East West Corporation
  - x. Inabata & Co. Ltd.
  - xi. Sumika Chemtex Co. Ltd.
- h. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. Anil Organics
  - ii. Aries Dye Chem Industries
  - iii. Aries Organics Private Limited
  - iv. Asiatic Colour-Chem Industries Pvt. Ltd.
  - v. Black Rose Industries Private Limited
  - vi. Cavendish Industries Limited
  - vii. Chemspark India Private Limited
  - viii. Endorse Chemicals LLP
  - ix. Innovassynth Technologies (India) Limited
  - x. J.K. Tyre & Industries Limited
  - xi. Madura Industrial Textiles Limited
  - xii. Rajsha Chemicals Private Limited
  - xiii. Roha Dye Chem Private Limited
  - xiv. Saraf Chemicals Private Limited
  - xv. Siddharth Colorchem Private Limited

- xvi. Singh Plasticisers and Resins (India) Private Limited
  - xvii. Somu Organo Chem Private Limited
  - xviii. Songwon Specialty Chemicals India Private Limited
  - xix. SRF Limited
  - xx. Techno Waxchem Private Limited
- i. In response to the initiation of the subject investigation notification, following importers/users have responded by filing questionnaire response:
- i. Black Rose Industries
  - ii. Somu Organo Chem Private Limited
  - iii. Taoka Chemical India Private Limited
  - iv. Techno Waxchem Private Limited
  - v. Alps Chemicals Pvt Ltd
- j. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- k. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- l. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7<sup>th</sup> March 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- m. Due to the change in the Designated Authority, a second oral hearing was conducted on 4<sup>th</sup> July 2025, which was attended by all the interested parties. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- n. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- o. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2023 to 31<sup>st</sup> March 2024. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods FY 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- p. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- q. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties.
- r. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 8<sup>th</sup> September 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- s. The Authority has considered all the relevant arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- t. An opportunity was provided by the Authority to all interested parties to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.
- u. ‘\*\*\*’ in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- v. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 83.69.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

- 4. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration.

*“The product under consideration is Resorcinol. The product under consideration is also known as 1,3-benzenediol; 1,3-dihydroxybenzene; 3-Hydroxyphenol; Resorcin Meta-Dihydroxybenzene and has a chemical formula C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>. The CAS number of the product under consideration is 108-46-3. The product under consideration comes in form of white to off-white flakes and is water soluble and conducive to derivatisation”*

**B.1. Views of other interested parties**

5. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.

**B.2. Views of the domestic industry**

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
  - i. There are three manufacturing processes, namely, Sulphonation-fusion process; Hydroperoxidation process; and MPDA hydrolysis process in order to manufacture the subject goods. The domestic industry uses Sulphonation-fusion process. The subject goods manufactured using different process are identical, have same specifications, and cater to the same consumers.
  - ii. The product produced by domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.

**B.3. Examination by the Authority**

7. The product under consideration in the present investigation is Resorcinol, also known as 1,3-benzenediol; 1,3-dihydroxybenzene; 3-Hydroxyphenol; Resorcin Meta-Dihydroxybenzene in the market parlance and has a chemical formula  $C_6H_6O_2$ .
8. The product under consideration can be manufactured using three manufacturing processes which include Sulphonation-fusion process, Hydroperoxidation process and MPDA hydrolysis process. The applicant has submitted that it is using Sulphonation-fusion process in order to manufacture the subject goods. The Authority notes that use of different production processes does not lead to any difference in the final product. The subject goods manufactured using different production processes are used for the same application and in the same manner, and there are no differences between the characteristics of the final product manufactured using different processes.
9. The product under consideration is classified under Chapter 29 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Code 2907 2100. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.
10. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are

different manufacturing process involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

## **C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

### **C.1. Views of other interested parties**

11. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing.

### **C.2. Views of the domestic industry**

12. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - i. The applicant is the sole producer of the subject goods in India and its production constitutes the entire Indian production for the subject goods.
  - ii. The applicant has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation.
  - iii. The applicant imported negligible quantity of subject goods from its related party in China during 2021-22.
  - iv. The applicant should be considered eligible to constitute domestic industry in the present investigation.

### **C.3. Examination by the Authority**

13. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

14. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Atul Limited which is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has submitted that it has not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. The Authority notes that that the applicant has a related entity in China PR. The applicant has submitted that it has imported a negligible quantity of [\*\*\*] MT of these product under consideration from the related party during 2021-22 for



R&D purposes. The Authority notes that the imports were made prior to the period of investigation, and thus, the applicant is eligible to constitute domestic industry.

15. In view of the foregoing, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

## **D. CONFIDENTIALITY**

### **D.1. Views of other interested parties**

16. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- i. The applicant has withheld key data, including segregated sales trends, amortization expenses, indexed cost breakdowns, etc., raising concerns about excessive confidentiality and transparency.
  - ii. The applicant has claimed excessive confidentiality regarding country-wise price undercutting, claiming the same as irrelevant in light of cumulative assessment, even when the Authority itself has disclosed country-wise price undercutting in case of Single Mode Optical Fiber, Electrogalvanized Steel and Jute products.
  - iii. The applicant has failed to disclose the source of normal value for Japan, and the adjustments made to third-country export price for arriving at the ex-factory normal value.
  - iv. As opposed to the submissions by the domestic industry, information with regard to affiliations of Black Rose, units linked to product under consideration, related company, channels of distribution and impact calculation is business sensitive information and cannot be shared.
  - v. Black Rock has provided reasonable summary of response regarded alleged injury to the domestic industry.

### **D.2. Views of the domestic industry**

17. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- i. The other interested parties have claimed publicly available information such as list of products sold confidential and have violated the requirements of Trade Notice 10/2018.
  - ii. Information which is normally disclosed in the final findings, such as channel of distribution and name of producers from which the subject goods have been purchased has been claimed confidential.
  - iii. A number of interested parties have provided post-invoicing discounts to the customers but have claimed the type of discounts as confidential.

- iv. Information with regard to adjustments claimed for fair comparison has been claimed confidential.
- v. The other interested parties have filed belated submissions on confidentiality.
- vi. The information with regard to determination of normal value for Japan has been provided to all the interested parties.
- vii. Since all the conditions of cumulation have been met in the present investigation, there is no need for providing country wise price undercutting.
- viii. The adjustments to third country export price for Japan have been made as per the facts available.

### **D.3. Examination by Authority**

- 18. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. The arguments of the parties with regard to confidentiality have also been examined hereinbelow.
- 19. The Authority notes that as per the initiation notification issued by the Authority, the deadline to file submissions on confidentiality was 7 days from the date of receipt of the non-confidential documents. The Authority notes that a number of interested parties have filed belated submissions on confidentiality.
- 20. With regard to the submissions that the applicant has not provided information with regard to determination of normal value for Japan, the Authority notes that the said information was provided as addendum to the application and was circulated to all interested parties.
- 21. With regard to the submissions that the other interested parties have failed to disclose certain information in their responses, the Authority notes that the interested parties have justified the confidentiality claimed by them. Further, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to non-disclosure of such information.
- 22. As regard submissions that the domestic industry has not provided country-wise price undercutting, the domestic industry has already provided the same vide letter dated 7<sup>th</sup> December 2024.
- 23. The other interested parties have submitted that the domestic industry has not provided the adjustments made to the third country export price of Japan for determination of normal value. The Authority notes that the domestic industry has provided the information filed on record in this regard in the non-confidential version. The adjustments made for export price were already disclosed. The Authority notes that the normal value for Japan has been determined based on the response filed by the cooperating producer. Hence, no prejudice has been caused to the interest of the other interested parties by non-disclosure of such information.

## **E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **E.1. Views of other interested parties**

24. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. Provisional duties are not warranted as the applicant has not demonstrated intensified imports, or urgent need for prevention of injury due to financial distress.
  - ii. In the previous investigation, benchmark form of duty for a tenure of 3 years was effective. The subject imports entered the domestic market at fair prices during the tenure of the previous duty and the domestic industry did not seek a sunset review. The same should be levied in the present investigation as well.
  - iii. The previous duty become redundant as the prices of Resorcinol increased significantly due to demand-supply gap in the market created due to closure of US plant.
  - iv. Anti-dumping duty, if imposed, should be done for a tenure of 2 years only. Even in the last investigation, there was no sunset review conducted which shows that the domestic industry was not suffering any injury. Post 2 years, a sunset review may be conducted, and the duty may be extended only if the domestic industry has supplied to all users and has not focused on captive consumption.
  - v. The applicant has not relied on DGCI&S data without proper reasoning for the same. This is an attempt to claim a higher quantum of import at a lower price.
  - vi. The application does not provide sufficient information to justify initiation of investigation.
  - vii. The investigation has been initiated without sufficient evidence of dumping as the applicant has not provided the details of export price for Japan to third country.

### **E.2. Views of the domestic industry**

25. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
- i. As opposed to the submissions by the other interested parties, there is no legal requirement to show intensified injury to justify interim duty.
  - ii. Contrary to the submissions of the other interested parties, reference price duty was ineffective in addressing dumping and injury as the reference price remained below the cost of production of the domestic industry. The domestic industry did not suffer injury during the said period due to other factors.
  - iii. The Authority may call for DG Systems or DGCI&S data and corroborate the data provided by the domestic industry.
  - iv. The other interested parties have not provided any information with regard to the claim that the application does not provide sufficient information to justify initiation.
  - v. There is no justification for imposition of anti-dumping duty for a period lesser than 5 years. This is especially relevant in the present case wherein; the Chinese Government has maintained fair prices in its domestic market by imposing anti-dumping duty on imports

from Japan. The other interested parties are free to approach the Authority for conducting a mid-term review post 2 years, in case of change in circumstances.

### **E.3. Examination by the Authority**

26. With regard to the submissions that there was no evidence for initiation of the investigation, the Authority notes that the applicant had provided prima facie evidence of dumping, injury and causal link. Only after undertaking prima facie examination of the evidence provided and duly satisfying itself with regard to the accuracy and adequacy of the evidence provided, the Authority initiated the present investigation. No information has been provided by other interested parties which would lead the Authority to conclude that the prima facie opinion drawn by it was erroneous.
27. The other interested parties have submitted that in case, anti-dumping duty is levied, the same should be for 2 years, and the duty should be in the form of a reference price. The Authority shall consider the tenure for which duty should be recommended and form thereof, if and when it concludes that there is a need for imposition of duty in the present case.
28. With regard to the submissions that the domestic industry has not relied upon the DGCI&S data, the Authority notes that certain products, falling outside the scope of the present investigation, are also being imported under the HS Code applicable to the product under consideration. The interested parties, including the domestic industry, do not have access to transaction wise DG Systems or DGCI&S data. The domestic industry has provided volume and value of imports, as per information reasonably available to it. However, for the purpose of the present investigation, the Authority has relied upon the DG Systems data. Hence, no prejudice has been caused to the interest of any interested parties by reliance by the domestic industry on market intelligence data.

## **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

### **E.4. Views of other interested parties**

29. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
  - i. China should not be treated as a non-market economy since Article 15 of the Accession Protocol has expired on 11<sup>th</sup> December 2016. As such, the practice of determining 'surrogate country' for normal value determination should not be used. Reference can be made to the recent Appellate Body report in EC-Fasteners (China).
  - ii. India is bound by the principle of "pacta sunt servanda" as a member of WTO and must recognize China's full market economy status from 11<sup>th</sup> December 2016. It cannot invoke domestic law as a justification for failure to perform.
  - iii. Until recently, US and EU also share the understanding that China should be treated as economic treatment post 2016. The explanatory memorandum issued by EU also

- shows that it shall treat China as a non-market economy for only 15 years after China enters the WTO. However, based on a bilateral agreement, the White House continues to treat China as a non-market economy.
- iv. The normal value for Japan and export price for both subject countries should be based on the questionnaire responses filed by participating producer/exporters.
  - v. The Japanese domestic market is not perfectly competitive and is influenced by presence of SCC being the sole established manufacturer and thus, normal value for the producer should be determined based on its cost of production and reasonable profits.
  - vi. Taoka Japan is not a producer of resorcinol but manufactures modified Resorcinol Formaldehyde Resin. Further, Taoka Japan did not export to India during the period of investigation.
  - vii. The applicant's price claims are flawed, with inflated normal value calculations and unsubstantiated ocean freight adjustments.
  - viii. The dumping margin claimed by the domestic industry is exaggerated. The domestic industry claimed normal value based on their cost, without any adjustment for different production process between their cost and other producers.

#### **E.5. Views of the domestic industry**

30. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
  - i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the AD Rules.
  - ii. Since the provisions of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol continue to remain in force, the producers in China PR are required to show that market economy conditions prevail.
  - iii. The Appellate Body in EC – Fasteners did not deal with specifically whether the entire provisions of Article 15(a) or only the provisions of Article 15(a)(ii) shall lapse on the expiry of 15 years.
  - iv. In all recent investigations, the Authority has considered China PR to be a non- market economy.
  - v. Contrary to the claims of the interested parties, European Union and USA continue to disregard domestic sales and cost of China PR. While China had approached the WTO Dispute Settlement Body regarding the same, but later suspended it.
  - vi. As opposed to the submissions of the other interested parties, China PR should not be treated as market economy as the Chinese producers have failed to establish that market economy conditions exist in their domestic market. The Chinese producers have not even filed market economy questionnaire response.
  - vii. The normal value has been provided by the domestic industry based on the information available at the time of filing the application.
  - viii. The claim of the Japanese producer that the market price is influenced by it being a sole producer, shows abuse of dominant position by the Japanese producer. However, there is no evidence that the consumers in Japan or competition authorities in Japan

- have investigated such abuse. The normal value for the producer must be determined as per provisions of Annexure-I and profits should be determined on the basis of sales made in ordinary course of trade.
- ix. The adjustments made by the domestic industry for determining net export price are as per information available. The other interested parties have not provided any evidence in this regard.
  - x. The response filed by Sumitomo Chemical Company should not be accepted as its related party, Taoka Chemical Company, has failed to participate in the present investigation. As per the website of the said entity, it is a producer of the product under consideration.
  - xi. The foreign producers are providing post invoicing discounts and have compensatory agreements with the customers. The Authority may verify the same.
  - xii. Techno Waxchem has imported resorcinol from Chinese exporter and exported the downstream product to the same entity. The price at which the downstream product has been exported to China PR is much lower than the price at which it has exported the same product to other countries. Further, Techno Waxchem has imported the subject goods at a higher price as compared to export of downstream product to China PR.
  - xiii. The price of imports by Black Rose are not reliable as it has an exclusive trading agreement with the Japanese producers. The import price of the product produced by the Japanese producers when imported from traders is much lower than the import price of Black Rose which has imported the said product directly from the producer. The price of SCC must be examined, and it must be ensured that the same is at arm's length.
  - xiv. The dumping margin is positive and significant.

#### **E.6. Examination by the Authority**

- 31. With regard to the submissions that the response filed by Sumitomo Chemical Company ("SCC") should not be accepted as its related producer has not participated, the Authority notes that the related party of SCC is not engaged in manufacturing of the subject goods. Thus, there is no need for the said producer to participate in the present investigation.
- 32. With regard to the submissions that there is a compensatory agreement and the producers are providing post invoicing discounts, the Authority notes that the export price has been determined based on verified information of the cooperating producers / exporters.
- 33. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

*"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

*ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market*

*situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*  
*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*  
*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*  
*(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

34. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
- i. Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd.
  - ii. Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.
  - iii. Zhejiang Dystar Trading Co., Ltd.
  - iv. Amino-Chem (HK) Co Limited
  - v. Sojitz Corporation
  - vi. Sumitomo Chemical Co. Ltd.
  - vii. B.R. Chemicals
  - viii. Songwon International – Japan K.K.
  - ix. East West Corporation
  - x. Inabata & Co. Ltd.
  - xi. Sumika Chemtex Co. Ltd.

## **E.7. Determination of Normal value and Export Price**

### **E.7.1. Normal value for China PR**

35. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a). In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the*

*manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b). In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c). The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d). Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

36. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
37. None of the sampled producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or*



*where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*

38. The applicant has claimed that the normal value should be determined on the basis of price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

#### **E.7.2. Export price for China PR**

##### **Export price for Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd.**

39. During the period of investigation, Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd. (Hongsheng) has exported \*\*\* MT to India, of which \*\*\* MT has been exported directly. The remaining volume has been exported through Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd. (Haicheng Chemical), and Zhejiang Dystar Trading Co., Ltd. (Dystar) further through Amino-Chem (HK) Co Limited (Amino HK) and Sojitz Corporation (Sojitz).

Hongsheng → Unrelated customers in India

Hongsheng → Haicheng Chemical (unrelated) → Unrelated customers in India

Hongsheng → Dystar (related) → Amino HK (related) → Sojitz (unrelated) → Unrelated customers in India

40. All the aforesaid exporters and traders have cooperated before the Authority. The Authority has determined the net export price based on the price charged from the first unrelated customer to India. The producer and exporters claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, port and handling charges, inland freight, bank charges and credit cost. The same have been allowed after desk verification. Further, losses of related exporters/trader have been adjusted. The landed price has been determined based on the price charged from the unrelated customer in India. The net export price so determined is mentioned in the table below.

##### **Export price for other producers/exporters in China PR**

41. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

### **E.7.3. Normal value for Japan**

#### **Normal value for Sumitomo Chemical Co. Ltd.**

42. During the period of investigation, Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Sumitomo) has exported \*\*\* MT of the product under consideration to India, while selling \*\*\* MT of the subject goods in the domestic market. The Authority notes that the domestic sales are sufficient in volumes when compared with exports to India, to determine the normal value based on domestic selling price. Sumitomo Chemical Co. Ltd. has sold the like article to related and unrelated customers in the domestic market. For related traders, the Authority has considered the resale price by the traders.
43. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Normal value has been determined based on the price of sales in the domestic market. SCC has claimed price adjustments on account of domestic insurance, inland freight, handling and loading charges and credit cost. The adjustments claimed have been allowed after desk verification. Thus, the normal value at ex-factory level has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.
44. With regard to the submissions that reasonable profits should be taken to determine normal value for SCC as the domestic market is influenced by SCC being a sole manufacturer, the Authority notes that there is no evidence of the fact that the said producer is charging unreasonable profits in its domestic market. The normal value has been determined as per the Anti-Dumping Rules.

#### **Normal value for other producers/exporters in Japan**

45. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

### **E.7.4. Export price for Japan**

#### **Export price for Sumitomo Chemical Co. Ltd.**

46. Sumitomo has exported \*\*\* MT of the product under consideration to India, of which \*\*\* MT has been exported directly. The remaining volume has been exported through B. R.

Chemicals (BRC) and East West Corporation (East West), and Songwon International – Japan K.K (Songwon). Songwon International – Japan K.K has, in turn, sold the goods to an affiliate, Songwon Specialty Chemicals-India Private Limited (Songwon India). The channels of exports are summarized below.

Sumitomo → Unrelated customers in India

Sumitomo → BRC (unrelated) → East West (unrelated) → Unrelated customers in India

Sumitomo → Songwon (unrelated) → Songwon India (related to Songwon) → Unrelated customers in India

47. All the aforesaid exporters, traders and related importer have cooperated before the Authority. The Authority has determined the net export price based on the price charged from the first unrelated customer. Further, adjustment has been made for the loss faced by the related importer of Songwon. The parties have claimed adjustments for ocean freight, ocean insurance, inland insurance, inland transportation, handling and transportation charges, finance / bank charges and credit cost. The adjustment claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The net export price determined is mentioned in the table below.

#### **Export price for other producers/exporters in Japan**

48. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

### **E.8. Dumping margin**

49. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

**Dumping Margin Table**

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	China PR					
1	Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***%	25-35
2	Others	***	***	***	***%	35-45
B	Japan					
3	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***%	30-40
4	Others	***	***	***	***%	50-60

**F. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK****F.1. Views of other interested parties**

50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- i. Consideration of 2020-21 as base year for injury analysis is incorrect as the prices during this period were very abnormally high due to INDSPEC's resorcinol plant shut down and impact of COVID-19.
  - ii. Cumulative assessment should not be done in the present case as the imports from China have increased till 2022-23, the imports from Japan have declined. Further, import price from Japan is higher than import price from China.
  - iii. The imports from Japan have declined post-duty expiry of anti-dumping duty which shows absence of volume injury.
  - iv. The volume of imports has declined in India while the demand has increased.
  - v. Loss in the market share of the domestic industry, if any, is on account of increased imports from China.
  - vi. The applicant has not provided information relating to price undercutting for first three years of injury period. In absence of such data, a causation analysis cannot be completed.
  - vii. The price undercutting claimed by the domestic industry is 0-10%, which shows that there no significant price disparity between selling price of the domestic industry and landed price of imports.
  - viii. The prices of Black Rose are much higher than the prices of the domestic industry.
  - ix. The applicant has aggressively reduced its prices forcing other suppliers in the market to reduce their prices in order to maintain market share.
  - x. The applicant has consistently been reducing its prices since the base year but is not gaining market share, which indicates that the customers are willing to import at higher prices as the applicant is an unreliable supplier.
  - xi. The increase in cost of sales of the domestic industry in the period of investigation is not in line with cost movement of other producers. The price of Benzene, the raw material constituting 50-60% of the cost, has declined during the injury period.
  - xii. The prices of subject goods from Japan remained stable in comparison to prices of both Atul and subject goods from China. Due to price pressure created by domestic industry and Chinese exporters, SCC was forced to reduce its prices in the period of investigation.
  - xiii. The applicant was able to increase its sales despite a decline in demand.
  - xiv. Atul has been more focused on production of its downstream products and exports and does not cater to the Indian market. Even when anti-dumping duties were in force, Atul's market share remained in the range of 10-20%.
  - xv. The domestic industry has shown improvement across key economic indicators, including production, and capacity utilization, undermining claims of material injury. Imports declined while domestic production rose, indicating no causal link between imports and losses.

- xvi. The inventories of the domestic industry have increased as it continued to increase its production despite decline in demand.
- xvii. While the number of employees has declined, the salary and wages have increased. The Authority may examine the same.
- xviii. The return on capital employed of the domestic industry declined due to increase in net fixed assets.
- xix. While the capital employed has increased, the installed capacity has remained unchanged. There is substantial increase in depreciation and net fixed assets. This raises questions on the credibility of data.
- xx. The reduction in profitability is due to aggressive trade distortive pricing strategy of the applicant.
- xxi. The Authority should verify the quantity of subject goods used captively, its valuation, the decision to sell the subject goods in the market or to use them captively, and the profitability of downstream products.
- xxii. The domestic industry's cost trends deviate from global patterns, with declining raw material prices contradicting rising production costs. Improved economic indicators, batch production inefficiencies, and outdated technology explain losses. The same was also acknowledged by the domestic industry in its AGM.
- xxiii. The applicant is facing injury on account of inefficient production process as sulphonation process is highly capital- and labour-intensive process, requires higher investment cost, has low-cost recovery through its by-products, higher utility cost and lower yield. As compared to this, SCC uses Hydroperoxidation process.
- xxiv. Use of obsolete technology cannot be considered as an inherent feature of the domestic industry as it has an option of improving its production process. Since development of technology is a relevant factor, it must be considered that use of obsolete technology is causing injury to the domestic industry.
- xxv. Injury to the domestic industry may be due to factors such as increased raw material costs, changes in market demand or inefficiencies in operation cost, and issues in inventory management.
- xxvi. The decline in profits was caused by an increase in the cost of sales due to increase in depreciation. Further, the domestic industry reduced its selling price despite low volume of imports.
- xxvii. Injury on account of decline in demand should not be attributed to imports. The reason for the decline in demand has also not been provided.
- xxviii. The applicant misrepresented operational stability, as its annual report confirms a month-long shutdown in 2020.
- xxix. The Authority may analyse other factors such as geographical location, challenges in raw material sourcing, high borrowing costs causing injury to the domestic industry.
- xxx. Factors such as Russia-Ukraine crisis, which have led to adverse effects on global demand and unprecedented increases in raw material and indirect material prices may have caused injury to the domestic industry.
- xxxi. The injury to the domestic industry is due to normalization of market post developments such as closure of Indspec, USA in 2017 leading to shortage of the product and increase in price and imposition of anti-dumping duty between 2018-

2021. Post COVID, the number of suppliers increased leading to normalization of price.
- xxxii. Prices globally have reduced which is evident from the fact that the domestic industry exports to Pirelli Tyre Co., Ltd in China. The prices of these exports have been reducing since 2021 and reached \$4.99/Kg during the period of investigation.
- xxxiii. The high injury margin claimed is on account of high cost and non-injurious price claimed by the domestic industry.
- xxxiv. The non-injurious price should be adjusted with regard to cost of by-product generated at par with value of by-product generated through other production process. The cost of utilities should be decreased by 8-10% to reflect cost of hydroperoxidation process.
- xxxv. A return of 22% should not be allowed on capital employed because such return is being allowed even on the debt portion of capital employed. Further, such return is very high in an era of global recession. A return of 22% on capital employed implies an effective profit on net worth of 27.15% to 41.41% depending upon the debt equity ratio.
- xxxvi. Return on capital employed of 22% should not be considered for determination of non-injurious price as the average return in the industry is not more than 10%. The EU for determination of price that would remove injury considers profit margin that could reasonably count on under normal conditions of competition, and in absence of dumping.
- xxxvii. The Drugs (Prices Control) Order, 1987 forms the basis of considering return at 22%. However, even such order considers that return of 14% may be allowed on net worth, or a return of 22% may be allowed on capital employed.
- xxxviii. A return of 22% was appropriate in the past when the interest rate was 18% and the corporate tax rate was 40%-50%. However, now that the interest rate has declined to 10% and corporate tax rate has declined 25%, such return is unjustified.
- xxxix. In the case of Bridgestone tire manufacturing, the CESTAT observed that adoption of a return of 22% on capital employed is not appropriate as inflates the injury margin. Similar view was taken by the CESTAT in the case of Houston Corporation versus Designated Authority.

## **F.2. Views of the domestic industry**

51. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- i. Contrary to the submissions of the other interested parties, all conditions for cumulative assessment have been met. Thus, the Authority may undertake cumulative assessment of injury.
  - ii. As opposed to the submissions of the other interested parties, movement of imports between the subject countries, inter-se changes in volume are not relevant and does not show lack of volume affect or injury. None of the other interested parties have shown that there is no need for cumulative assessment.

- iii. There is a demand-supply gap in the country. Till the time the imports were fulfilling the demand-supply gap, the domestic industry was not suffering injury. However, the imports have increased at low-prices to take away the market share of the domestic industry.
- iv. The volume of imports has further increased post the period of investigation and has taken away the market share of the domestic industry.
- v. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- vi. Price undercutting has increased post the period of investigation.
- vii. Price undercutting analysis is only relevant for the period of investigation and not for the injury period.
- viii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the price undercutting is not high as resorcinol is a commodity product and the domestic industry is forced to match the prices of imports.
- ix. The landed price of the subject imports has declined significantly over the injury period. The decline in landed price is not commensurate to change in cost of raw material.
- x. The landed price in India has declined more than the decline in export price globally.
- xi. The gap between the variable cost of the domestic industry and landed price of the subject imports has declined.
- xii. The domestic industry is not aware of prices or cost structure or prices of Black Rose. As opposed to the submissions of the other interested parties, only the price of the exporter is relevant and not the unrelated Indian trader. This is due to the fact that the Indian industry is competing with prices of the exporter as nothing bars the importer from purchasing from another source in the absence of dumping. Even in case of a related importer, the Authority does not consider resale price for injury analysis.
- xiii. As opposed to the submissions by the other interested parties, the capacity of the applicant is less than the Indian demand and hence, has no incentive to reduce prices.
- xiv. Positive price undercutting shows that prices were reduced by exporters and not the domestic industry.
- xv. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- xvi. The cost of raw material has increased over the injury period as evident from the import price of raw material.
- xvii. The domestic industry was forced to reduce its prices in order to keep its plant operational and maintain a market share. In case, the domestic industry would not have reduced prices, it would have suffered in terms of domestic sales and market share.
- xviii. The domestic industry has reduced its cost by making investments in effluent treatment plant which has resulted in decline in conversion cost. Even though the conversion cost has declined, the domestic industry has not benefitted from such decline as it has been forced to reduce selling price more than such decline.

- xix. As opposed to the submissions by the other interested parties, SCC is making huge profits in its domestic market and hence, even if it is selling at losses in the export market, its viability is good. Thus, SCC has reduced price in India.
- xx. As opposed to the submissions of the other interested parties, the benchmark form of duty was ineffective as the benchmark was below the cost of production of the domestic industry. The domestic industry has been able to improve its economic parameters due to absence of dumping during the tenure of the anti-dumping duty.
- xxi. The domestic industry was able to increase its sales only due to selling the subject goods at losses.
- xxii. The domestic sales of the domestic industry and market share has decline post the period of investigation.
- xxiii. Despite having capacity to cater to more than 50% market share, the market share held by the domestic industry is much less.
- xxiv. The inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period and the inventory holding period of the domestic industry has increased.
- xxv. Increase in inventory despite demand-supply gap itself establishes injury to the domestic industry. In case, there was no dumping in India, the domestic industry would have been able to liquidate its entire stock.
- xxvi. The domestic industry has incurred losses in the period of investigation. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.
- xxvii. The injury to the domestic industry is evident from decline in profits, cash profits, return on investment and growth.
- xxviii. The profitability of the domestic industry has further declined post period of investigation.
- xxix. The domestic industry has incurred losses even before providing for interest. Thus, it has not even earned enough to meet its interest obligations.
- xxx. Contrary to the submissions by other interested parties, there is no aggressive trade distorting pricing by the domestic industry. This is evident from the fact that there are only three producers globally and the demand in India is more than the capacity of the domestic industry.
- xxxi. As opposed to the submissions of the other interested parties, if return on investment is determined by considering NFA of the base year, the same will still show a significant deterioration over the injury period.
- xxxii. The present situation is not conducive of any new investments. The domestic industry has been able to survive as its plant is fully depreciated. In case of a new investment, the producer will not be able to earn any return on investment.
- xxxiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the claim of injury is based on actual records of the applicant. The exporters have not established based on its data that the decline in export price is due to decline in cost and its domestic selling price.
- xxxiv. As opposed to the submissions of the other interested parties, even the PBDIT of the domestic industry, which does not include depreciation, has also declined. Thus,



- the injury is not due to increase in depreciation. In any case, depreciation is a bonafide expense of the domestic industry and cannot be disregarded.
- xxxv. Contrary to the submissions of the other interested parties, the injury to the domestic industry is not due to decline in demand as the demand in India is much higher than the capacities of the applicant.
- xxxvi. The other interested parties have identified inherent features of the domestic industry. Since there is no change in such factors over the injury period and the applicant was profitable in the past, injury is not attributable to such factors.
- xxxvii. The claim that the technology used by domestic industry is obsolete is a mere statement as the other interested parties have not provided even a single factor making such technology obsolete.
- xxxviii. Difference in technology of SCC and the applicant is irrelevant as the other interested parties have been dumping in India irrespective of the technology used.
- xxxix. While the other interested parties have pointed out shutdown in 2020, which was due to COVID-19, as a reason for injury, injury has been claimed in the period of investigation and not in 2020.
- xl. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is no impact of Russia-Ukraine crisis on the domestic industry. Further, increase in raw material cost should lead to increase in prices of the subject goods in normal business scenario. The decline in prices is due to dumping in India.
- xli. As opposed to the submissions of the other interested parties, injury to the domestic industry is established by comparison of period of investigation with any of the previous year and not just the base year.
- xl.ii. Contrary to the submissions that price reduction is due to normalization of markets, the producers in the subject country are dumping the product in India due to which the prices have reduced in India.
- xl.iii. The applicant has been able to fetch fair prices in China as the Government of China has maintained fair prices in domestic market and has imposed anti-dumping duty on imports from Japan into China.
- xl. iv. The non-injurious price should be determined as per Annexure III. Contrary to the submissions of the other interested parties, Annexure III requires Authority to consider the financial data of the applicant only.
- xl. v. The other interested parties have considered artificial debt equity ratio for submissions regarding return on capital employed. The actual ratios may be quite different.
- xl. vi. Reference to Drugs Control Order, 1987 is not appropriate as it allowed an addition to the total cost of production. However, the Authority considers an artificially suppressed cost and therefore, non-injurious price may not even allow recovery of full cost of the domestic industry.
- xl. vii. Principles laid down by CESTAT with regard to consideration of 22% return on capital employed should be followed for determination of non-injurious price. In Bridgestone Tyre Manufacturing case, the other interested parties had brought evidence that global returns were lower. Post this decision, the CESTAT has held 22% return is justified in a number of decisions.

- xlvi. Contrary to the submissions by the other interested parties, there is a difference between determination of fair selling price by EU and the Indian Authority. EU determines the fair selling price based on total cost of production without adjustments for optimisation of raw materials, utilities and capacities and all expenses incurred by the domestic industry. Therefore, fair selling price considered by EU, allows full recovery of cost plus some profit.

### **F.3. Examination by the Authority**

52. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
53. With regard to the submission that 2020-21 should not be considered as the base year as the prices were abnormally high during this period, the Authority notes that for the purpose of injury analysis, comparison has been made by 2020-21, 2021-22 and 2022-23. The domestic industry shows deterioration in performance as compared to any of the previous years. Thus, the injury to the domestic industry is not just based on comparison with the base year.
54. The Authority further notes that while the landed price of the subject imports has remained higher than the cost of sales of the domestic industry in the injury period including 2020-21, 2021-22 and 2022-23, it has declined to a point below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation. The said landed price cannot be considered to be due to normalization of market post closure of the US producer. Further, as per the responses filed by the producers in the subject countries, the said producers are dumping the product under consideration in India. Thus, in any case, such prices cannot be considered fair in the Indian market.
55. With regard to the submissions that the prices normalized in the period of investigation due to increase in the number of suppliers post COVID-19, the Authority notes there are only three producers of the subject goods including the applicant. All three producers have been in operation since a long time and no new producer has set up production of the subject goods post COVID-19. Thus, the submission that the prices declined due to increase in suppliers is incorrect.
56. With regard to the submissions that the prices of Black Rose should be considered for injury analysis and not that of the exporter, the Authority notes that in order to conduct injury analysis, the Authority considers the import price into India and the price at which the domestic industry is competing with the imports. The Authority further notes that while Black Rose is an exclusive trader for the producer in Japan, the domestic industry actually competes with the import price of the producer and exporters from Japan. This is evident from the fact that in the absence of dumping, the importers in India were free to source from the domestic industry.

57. With regard to the submissions that there is doubt on credibility of data submitted by the applicant as installed capacity has remained unchanged while capital employed, net fixed assets and depreciation has increased, the Authority notes that the data submitted by the domestic industry has been verified. Further, the Authority has relied upon the verified data of the domestic industry for the purpose of the present investigation.
58. With regard to the submissions that there is demand-supply gap in India, the Authority notes that demand-supply gap is not a justification for dumping in India. The present investigation was initiated based on prima facie evidence of dumping of subject goods in India. Even though there is a demand-supply gap, dumping is an unfair trade practice due to which the sole producer in India is suffering material injury. The response filed by the foreign producers and exporters shows that the dumping margin is positive and significant.
59. As regard the submissions that the Authority should verify the profitability of the downstream product of the domestic industry, the Authority notes that the present investigation has been initiated with regard to dumping of subject goods from the subject countries and the injury suffered by the domestic industry due to such dumping. Since the Authority has examined dumping, injury and causal link with regard to the subject goods, there is no requirement to check the profitability of the downstream product. Further, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the applicant benefitted in the downstream product during the time the prices of product under consideration were higher.

### **F.3.1.Cumulative assessment of injury**

60. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
61. In the instant case, volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than the *de-minimis*. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.

62. With regard to the submissions that the import price from one of the subject countries was higher than other subject country and that imports from one of the countries has increased while the other has declined, the Authority notes that there is no requirement to assess the same for cumulation of imports. The Authority notes that in all investigations where imports from more than one country are simultaneously being assessed, the import price from one of the countries will always be higher than the other.
63. The Authority thus, concludes that it would be appropriate to undertake cumulative assessment of injury in the present investigation for the following reasons.
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
  - The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
  - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
  - Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

### **F.3.2. Volume effect of the dumped imports**

#### **a) Assessment of demand / apparent consumption**

64. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
<b>Excluding Captive</b>					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	110	151
Imports from subject countries	MT	4,199	4,951	5,013	4,211
Imports from other countries	MT	11	3	21	-
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	118	107
<b>Including Captive</b>					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	115	140
Imports from subject countries	MT	4,199	4,951	5,013	4,211
Imports from other countries	MT	11	3	21	-
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	118	111

65. The Authority notes that the demand for the subject goods in India including captive consumption as well as excluding captive consumption has increased year on year till 2022-23. The demand has declined in the period of investigation as compared to the previous year. However, the demand including and excluding captive consumption has remained high in the period of investigation as compared to demand in the base year.

**b) Import Volumes from the subject countries**

66. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes from subject countries during the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from subject countries	MT	4,199	4,951	5,013	4,211
Imports from China PR	MT	1,809	2,453	2,443	1,709
Imports from Japan	MT	2,390	2,498	2,571	2,502
Imports from other countries	MT	11	3	21	-
Total Imports	MT	4,210	4,954	5,034	4,211
Subject imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	107	82
Consumption/Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	101	94
Total imports	%	99.7%	99.9%	99.6%	100%

67. The Authority notes that:
- The volume of imports from the subject countries increased in 2021-22 and 2022-23 as compared to the base year but declined thereafter in the period of investigation. The volume of subject imports has remained higher in the POI than that in the base year.
  - Imports in relation to production and consumption have also declined over the injury period.
  - The imports from subject countries account for entirety of imports into India during POI.
68. With regard to the submissions that the imports from Japan have declined post expiry of anti-dumping duty, the Authority notes that the imports from Japan have increased over the injury period. In any case, since all conditions for cumulative assessment have met in the present investigation, there is no requirement for examining trend of imports from individual subject countries.

**F.3.3. Price effect of the dumped imports**

69. With regard to the price effect of the imports from the subject countries, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

**a) Price undercutting**

70. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

Particulars	Unit	China PR	Japan	Subject countries
Selling price	₹/MT	***	***	***
Landed price	₹/MT	4,70,672	4,46,947	4,56,574
Price undercutting	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%

71. The Authority notes that the subject imports are priced below the selling price of the domestic industry. The price undercutting from all subject countries is positive and significant.

**b) Price suppression/depression**

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	147	122
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	78	57
Landed price	₹/MT	7,26,622	6,55,797	6,39,486	4,56,574
Trend	Indexed	100	90	88	63

73. The Authority notes that while the cost of sales of the domestic industry has increased over the injury period, the selling price has declined significantly. The landed price has also declined over the injury period. Further, while both cost of sales and selling price has declined in the period of investigation as compared to the previous year, the selling price has declined more than decline in cost of sales. Thus, landed price of subject imports has suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
74. With regard to the submissions that the domestic industry has reduced prices forcing the exporters to reduce prices, the Authority notes that the demand in India is higher than the capacities of the domestic industry. In such a case, there is no incentive for the domestic industry to reduce prices. In any case, the landed price of the subject imports is priced below the cost of sales of the domestic industry which has forced the domestic industry to sell at prices below its cost of sales and incur financial losses.
75. The Authority notes that the cost of raw material has increased over the injury period except in POI. However, the selling price of the domestic industry as well as the landed price of subject imports has declined. Further, the gap between the raw material cost of the domestic industry and landed price of subject imports has declined over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Landed price	₹/MT	7,26,622	6,55,797	6,39,486	4,56,574
Raw material cost	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	125	69
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Gap between landed price and raw material cost	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	66	57	41

#### **F.3.4. Economic parameters of the domestic industry**

76. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

##### **a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes**

77. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	112	122
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	112	122
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	110	151
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	73	86
Captive Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	120	132

78. The Authority notes that:
- The installed capacity of the domestic industry has remained stable throughout the injury period.
  - The production, capacity utilization as well as domestic sales of the domestic industry has increased over the injury period.
  - The export sales of the domestic industry increased in 2021-22 as compared to previous year and declined thereafter. The export sales have declined over the injury period.
  - The captive consumption of the domestic industry has increased year on year over the injury period.
79. Authority notes that despite of 22% increase in the production in the POI from the base year, domestic sales of domestic industry have increased by 51% in the POI from the base year. This is in contradiction to the submission of the interested parties that domestic industry is an unreliable supplier. Further, the demand quantified by the Authority includes both captive consumption of the applicant and merchant demand. In case, the applicant ceases captive consumption of the subject goods, it will have to import the subject goods in India. In such a case, captive consumption of the applicant does not change the merits of the present investigation.
80. It is also seen that the captive consumption of the domestic industry increased by 32% over the injury period, however, domestic sales of the domestic industry increased by 51% over the injury period.
81. The Authority notes that the domestic industry has submitted that due to increase in low-priced imports, the domestic sales and market share of the domestic industry has declined post period of investigation.



**b) Market share in demand**

82. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	93	141
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	101	94
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	50	200	0

83. The Authority notes that the market share of the domestic industry declined slightly in 2022-23 and increased thereafter in the period of investigation. The applicant has submitted that the market share of the domestic industry has increased as the domestic industry has sold at losses due to the presence of low-priced imports in India. Due to this, the market share of the domestic industry has increased and that of the subject imports has declined in the period of investigation.

84. With regard to the submissions that the applicant is an unreliable supplier as it has not gained market share even though it has reduced prices, the Authority notes that the market share of the domestic industry has increased in the period of investigation as it significantly compromised on its profitability.

**c) Inventories**

85. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	313	249

86. The Authority notes that the inventories of the domestic industry has increased significantly over the injury period. While there is ample demand in India, the domestic industry has suffered due to accumulation of inventories.

**d) Profitability, cash profits and return on capital employed**

87. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	147	122
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	78	57
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	45	10	(6)
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	53	11	(9)
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	57	17	0.89
Return on capital employed	%	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	42	7	(6)

88. The Authority notes that:

- The profitability of the domestic industry has declined significantly in the POI as compared to the previous year as well as the base year. While the domestic industry was earning profits during the previous years, it has incurred financial losses during the period of investigation.
- The cash profits have followed the same trend and has declined year on year throughout the injury period. Cash profits earned by the domestic industry were lowest during the period of investigation.
- The return on capital employed of the domestic industry has also declined throughout the injury period. The domestic industry has recorded negative return on capital employed during the period of investigation.

89. With regard to the submissions that the return on capital employed has declined only due to increase in net fixed assets, the Authority notes that the domestic industry has incurred losses during the period of investigation. The return on capital employed is negative considering net fixed assets for any of the previous periods as well. Thus, the decline in return on capital employed is not due to increase in net fixed assets.

90. As regard the contention that the profitability of the domestic industry has declined due to increase in depreciation cost, the Authority notes that the EBDITA of the domestic industry, which does not include depreciation, has also declined over the injury period. Thus, the decline in profitability of the domestic industry is not due to increase in depreciation cost. Further, the domestic industry has submitted that post period of investigation, the profitability of the domestic industry has further declined.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
EBDITA	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	15	1

**e) Employment, productivity and wages**

91. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	95	94
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	112	122
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	118	130
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	108	120

92. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have declined slightly over the injury period. The productivity as well as salary and wages of the domestic industry have increased.

#### f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	%	-	-	-	-
Production	%	-	23	(9)	9
Domestic sales	%	-	18	(7)	38
Profit / (loss) per unit	%	-	(55)	(78)	(162)
Cash profits	%	-	(52)	(68)	(96)
Return on capital employed	%	-	(58)	(83)	(188)

93. The Authority notes:

- The capacity of the domestic industry has not changed over the injury period.
- The volume parameters of the domestic industry showed positive growth in 2021-22 but declined in 2022-23. The volume parameters show a positive growth in the period of investigation. The domestic industry has submitted that the volume parameters have shown positive growth as the domestic industry has compromised on its profitability.
- The profitability parameters of the domestic industry show a negative growth year on year, throughout the injury period.

#### g) Factors affecting prices

94. Since the price of subject imports is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry, the same has created a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are priced below the non-injurious price of the domestic industry. Due to this, the domestic industry has not been able to price its product commensurate to change in its cost of sales. Therefore, the imports from the subject countries are impacting the prices of the domestic industry.

**h) The magnitude of dumping**

95. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

**i) Ability to raise capital investments**

96. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation. The return on capital employed of the domestic industry was negative in the period of investigation. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted. The Authority further notes that the present prices are not conducive of any new investments.

**j) Magnitude of Injury Margin**

97. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
98. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
99. As regard the contention that 22% return on capital employed is unwarranted, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%, barring when there is evidence on record that 22% should not be considered and some other figure is more appropriate. In the present case, no evidence has been provided by other interested parties that a return of less than 22% would be appropriate for the product under consideration. The observations of the Hon'ble CESTAT in the Bridgestone case were specific to the use of 22% ROCE in determining price underselling, not its appropriateness in computing the Non-Injurious Price (NIP). Moreover, the Bridgestone decision predates the introduction of Annexure-III to the AD Rules, rendering reliance on it by other interested parties unjustified. In the subsequent Merino Panel Products case, the CESTAT upheld the practice of the Authority of applying a 22% return on capital employed.

100. With regard to the submission the non-injurious price should be adjusted to reflect cost of hydroperoxidation process, the Authority notes that the non-injurious price is determined as per the provisions of Annexure III to the Anti-Dumping Rules. As per Annexure III, the data of the domestic industry has to be considered.
101. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
A	China PR					
1	Zhejiang Hongsheng Chemical Co. Ltd	***	***	***	***%	15-25
2	Others	***	***	***	***%	30-40
B	Japan					
3	Sumitomo Chemicals Co. Ltd	***	***	***	***%	15-25
4	Others	***	***	***	***%	35-45

### F.3.5. Non-attribution analysis and casual link

102. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

#### a. Volume and value of imports from third countries

103. It is noted that subject imports constitute entirety of imports into India during the period of investigation. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

#### b. Contraction in demand

104. The demand for the subject goods has declined over the injury period. However, the demand in India is much higher than the capacities of the domestic industry. Hence, the injury to the domestic industry is not attributable to contraction in demand.

#### c. Pattern of consumption

105. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

#### d. Conditions of competition and trade restrictive practices

106. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have cause injury to the domestic industry.

**e. Developments in technology**

107. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.
108. With regard to the submissions that the injury is due to inefficient production process of the domestic industry, the Authority notes there is no change in the production process employed by the domestic industry during the injury period. The production process of the domestic industry is an inherent feature of the domestic industry. The Authority notes that non-attribution analysis is not required to be conducted for factors inherent to the domestic industry, which have remained unchanged over the period. The domestic industry has not suffered injury in the previous year even though it was operating with the same technology and production process as that in the period of investigation. Thus, injury is not attributable to the inherent feature of the domestic industry.

**f. Productivity**

109. The total production of the domestic industry including production for captive consumption has increased over the injury period. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

**g. Export performance of the domestic industry**

110. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

**h. Performance of other products**

111. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

**i. Shut down of other producers globally and COVID-19**

112. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to COVID-19 and increase in suppliers post COVID-19, the Authority notes that there are only three producers of the subject goods globally. Further, the demand in India is higher than the capacity of the Indian industry. Thus, there has neither been increase in number of suppliers nor there is oversupply in the market causing injury to the domestic industry.
113. The Authority further notes that the US based producer shut down in 2017. Any impact of such shutdown would have been relevant in the past. There is no evidence of impact of such shutdown on the domestic industry in the period of investigation.

**j. Increased cost of raw material due to Russia-Ukraine crisis**

114. The other interested parties have submitted that injury is due to increase in cost of raw material due to Russia-Ukraine crisis. The Authority notes that there is no evidence on

record that Russia-Ukraine crisis led to an adverse impact on the domestic industry. In any case, such impact is applicable to all producers globally and not just the domestic industry.

115. The Authority further notes that in a normal business scenario, the selling price of the subject goods should fluctuate in accordance with the price of the raw material. The same has not been observed in the present case. As noted hereinabove, while cost of sales has increased, the selling price has declined. Thus, no injury is attributable to price of raw material.

## **G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

### **G.1. Submissions by other interested parties**

116. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. The applicant's impact analysis focuses only on the tyre industry, ignoring other affected sectors like dyes, pharmaceuticals, and agrochemicals. Increased resorcinol costs will raise prices across multiple industries, worsening inflation and reducing competitiveness.
  - ii. The domestic industry has miscalculated the impact of anti-dumping duties on the tyre industry instead of immediate downstream users.
  - iii. The domestic industry has calculated the impact of duties based on SION norms but have only considered consumption of Resorcinol in the tyre, while ignoring consumption of resins and fabric, which are produced using and dipped in Resorcinol, respectively.
  - iv. Imposition of duties would lead to increase in cost of the subject goods by 10-15% and would result in reduction of profits of downstream users by 90-100%.
  - v. Imposing duties would allow Atul to dominate the domestic market, disadvantaging competitors in downstream products. Atul's refusal to supply certain buyers and its preference for exports further justifies the need for continued imports.
  - vi. With the closure of INDSPEC plant in 2017, there are only three resorcinol manufacturers in the world (China, Japan and India) and thus, there is no question of subject imports obliterating imports from other countries.
  - vii. Atul lacks the capacity to meet domestic demand and does not offer a stable supply chain. In contrast, importers provide reliability, ensuring smooth industrial operations. Anti-dumping duties would lead to price hikes, supply disruptions, and reduced trust in Indian suppliers.
  - viii. During the global resorcinol shortage in 2017, the domestic industry increased its prices and refused to supply volumes to the users. The Japanese producer supplied the product under consideration to Indian users in the said period. Imposition of anti-dumping duty will make the user industry uncompetitive in the global market.
  - ix. Despite the imposition of anti-dumping duties, the applicant did not make effort to increase its production capacity to cater to the Indian demand. The actual remedy to the domestic industry will be reduced demand-supply gap. During the oral hearing,

- while the applicant submitted that it is planning capacity expansion, no concrete details have been shared. In the absence of capacity expansion, the present case should be terminated in the interest of users.
- x. Indian resorcinol behaves differently in dye synthesis as compared to imported resorcinol, hence forcing users to depend on imports to meet their requirements.
  - xi. The domestic industry relies on the outdated sulfonation fusion process, which is environmentally harmful.
  - xii. In its user profitability analysis, the domestic industry wrongly mentioned figures relating to Techno Waxchem in 'crores' when they were in 'lakhs'.

## **G.2. Submissions by the domestic industry**

117. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
- ii. The impact quantified by the domestic industry is for the major consumer segment for the product under consideration. While the other interested parties have claimed higher impact in other segments, the users in such segments have not participated in the present investigation.
- iii. The impact cannot be calculated on the immediate downstream industry as it passes on the increase in cost of the product under consideration to its downstream industry. This is evident from the fact that the profitability of Techno Waxchem has not been adversely impacted due to high prices of the product under consideration in the past. The impact has thus, been calculated on the industry which bears the impact of the anti-dumping duty.
- iv. Since the product is not sold at retail level and the prices of the tyre industry does not fluctuate due to change in price of resorcinol, there will be no adverse impact on the final consumer of the product.
- v. The impact has been quantified with regard to increase in cost of the product under consideration in the downstream product. All other parameters have been kept at the same level.
- vi. Since resorcinol is a commodity product, there is no difference between the subject goods supplied by the domestic industry and those imported from the subject countries. The consumers are able to switch the suppliers based on the prices being offered.
- vii. As opposed to the submissions of the other interested parties, imposition of anti-dumping duty will not unduly benefit the applicant for downstream products as it transfers the subject goods for downstream production at market driven prices.
- viii. The applicant has refused supply only in cases where the consumers demanded unfairly low prices. The consumers have taken price quotes from the applicant and negotiated prices with the exporters.



- ix. Post closure of the US producer, the consumers approached Atul as there was lack of supply globally. While the applicant was unable to supply at that point as it was catering to regular customers, it shows importance of domestic production in the country.
- x. As opposed to the submissions of the other interested parties, the increase in prices post closure of the US producer was due to the demand-supply forces in the market. The price of the subject goods increased not only for the domestic producer but for producers globally and even producers from China and Japan increased prices. Similar situation may be created if dumping is not checked and the domestic industry is forced to cease production.
- xi. The applicant has expanded capacities as compared to the period in the previous investigation. The applicant has further planned on expansion of capacities.
- xii. As opposed to the submissions of the other interested parties, even if the domestic industry did not plan capacity expansion, it does not preclude the domestic industry from seeking remedy against unfair trade practices.
- xiii. China maintains fair market conditions in its domestic markets which is evident from the fact that it has imposed anti-dumping duty on imports from Japan. Further, in the past, there was an anti-dumping duty imposed by China on imports from USA as well.
- xiv. Contrary to the submissions of the other interested parties, demand-supply gap cannot be a reason for non-imposition of duties. Imposition of anti-dumping duty will not lead to ban on imports into India. The Authority in a number of previous cases, wherein there was a demand-supply gap, has recommended imposition of anti-dumping duty.
- xv. Contrary to the submissions of the other interested parties, imposition of anti-dumping duty will not make downstream industry uncompetitive as only the Indian downstream industry has access to lower priced raw material as compared to downstream industry in other countries. Further, for the purpose of exports, the downstream industry can import the product under advance authorisation without payment of anti-dumping duty.
- xvi. As opposed to the submissions that domestic product behaves differently for dye synthesis, the domestic industry has been supplying to customers in dye synthesis segment.
- xvii. The product is highly capital intensive and the market situation is not conducive of any new investments.
- xviii. Contrary to the submissions of the domestic industry, since there are only 3 manufacturers globally, it is important to establish fair market prices in India, in order for the domestic industry to maintain its viability.
- xix. The small-scale users are able to purchase smaller quantities from the domestic industry. However, they will not be able to directly import such small quantities and will be forced to pay higher prices to the traders.
- xx. The combined capacity of Chinese and Japanese producers is higher than the domestic demand in their country. India is a lucrative market due to which producers in the subject countries have reduced prices for exports to India.
- xxi. Contrary to the submissions of the other interested parties, the plant of the applicant has not been found harmful by the competent authorities in India.

- xxii. Since the product under consideration forms insignificant part of tyre industry, the tyre manufacturers as well as tyre cord fabric manufacturers have not participated in the present investigation.
- xxiii. Techno Waxchem exports the subject goods to China at prices much lesser than that to other countries. There is either a compensatory agreement or there are high margins involved in the product which allows Techno Waxchem to charge lesser prices.
- xxiv. The economic parameters of the domestic industry have been adversely impacted in the period of investigation due to imports at low prices. The volume as well as price parameters have further deteriorated post period of investigation.
- xxv. The applicant promotes Aatma Nirbhar Bharat and domestic procurement of raw material.

### **G.3. Examination by the Authority**

- 118. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily, rather it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the imposition of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain intact by the imposition of these measures. The imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
- 119. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
- 120. The Authority notes that the product under consideration is a commodity product which is evident from the fact that the landed price and selling price of the domestic industry move in tandem. Since it is a commodity product, the users are able to switch suppliers easily and there are no long approval requirements.
- 121. There are only three producers of the subject goods globally. The Authority notes that while the domestic industry has the capacity to cater to [\*\*\*]% of the total demand in India, its market has been below \*\*\*% during the period of investigation. There are no alternative sources of supply available for the downstream industry. Thus, in such a case, it is essential to maintain the viability of the domestic industry.

122. The Authority notes that there is a demand-supply gap in India and there is a need for further investments in production of the product under consideration. The domestic industry has submitted that the plant for production of the product under consideration is highly capital intensive. In order to produce the subject goods, a producer is required to invest ₹ [\*\*\*] crores for a capacity of [\*\*\*] MT for a brown field investment. The Authority notes that the return on capital employed of the domestic industry is negative and thus, investment for any new plant is not feasible.
123. The Authority notes that the domestic industry has shared plans for capacity expansion in order to bridge the demand-supply gap. However, such investments are not possible due to the current market situation. The domestic industry has incurred financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. In such a situation, the applicant or any other producer is not likely to invest in India.
124. With regard to the submissions that there is demand-supply gap in India, the Authority notes that demand-supply gap is not a justification for dumping in India. The Authority has determined the dumping margin based on the response filed by the foreign producers and exporters. The dumping margin is positive and significant. Further, demand-supply gap in India does not bar the Authority from recommending imposition of anti-dumping duty.
125. The other interested parties have stated that the domestic industry has refused supply of the product to the downstream industry. The domestic industry has submitted that the refusal to supply was due to extreme shortage of the material globally at the time of closure of the US producer, however, even at that time, the domestic industry did not refuse supply to regular customers. The domestic industry has further stated that the submissions have been made by users who have always relied upon imports of the product and approached the domestic industry only during the shortage period. The Authority notes there is a demand-supply gap in India. Imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports of the product into India but only ensure that the same are available at fair prices.
126. With regard to the submissions that the applicant focuses on captive consumption and export market, the Authority has already noted that the demand-supply gap does not bar the Authority from recommending imposition of anti-dumping duty.
127. With regard to the submissions that imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of the downstream industry making it unviable, the Authority notes that viability of the downstream industry cannot be dependent upon dumped prices of the product under consideration. In any case, as per the evidence on record, the immediate downstream industry for the product under consideration is pass through in nature. The prices of the downstream product changes with change in price of the product under consideration.
128. The Authority notes that China has imposed anti-dumping duty on imports of the product under consideration from Japan in order to maintain fair prices in its own market. Thus, protecting the sole producer of the product under consideration in China.

129. With regard to the submissions that the applicant is competing with downstream manufacturers and will unduly benefit by imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the applicant benefitted during the time the prices of product under consideration were higher. Further, the domestic industry has submitted that it transfers product under consideration to the downstream industry at market driven prices. Thus, there will be no unfair advantage to the applicant in the downstream product.
130. With regard to the submissions of the other interested parties that imposition of anti-dumping duty will make downstream industry uncompetitive, the Authority notes that the product under consideration is currently available to the Indian downstream industry at dumped prices. There are only three manufacturers of the product under consideration globally. Since the price of the product under consideration in China PR and Japan is higher than the price of the product under consideration in India, the Indian user industry will not become uncompetitive viz-a-viz downstream industry in other countries. With regard to performance of downstream industry in export market, the Authority notes that in order to export the downstream product, the user industry can import the product under consideration under advance license without payment of anti-dumping duty.
131. With regard to the submissions that Indian resorcinol behaves differently for dye synthesis, the Authority notes that as per evidence on record, the domestic industry has been supplying the subject goods to dye synthesis segment. Since the users have purchased the subject goods from the domestic industry regularly, there is no doubt on acceptability of the product manufactured by the domestic industry for the said segment.

## **H. POST DISCLOSURE COMMENTS**

### **H.1. Submissions by other interested parties**

132. The other interested parties have made the following submissions on the disclosure statement issued:
- i. The petition does not contain the evidence of adjustments claimed for determination of normal value and the applicant has claimed excessive confidentiality in this regard.
  - ii. The Authority has not provided the reason for disparity in imports from Japan provided in the disclosure statement and that provided by the applicant in the application.
  - iii. The prices in Japan are higher due to SCC being the only producer in the country. SCC is able to charge premium in the domestic market as it is the sole supplier in Japan.
  - iv. Price undercutting should be assessed for the complete injury period.
  - v. The decline in prices in the Indian market is due to normalization of market which is evident from the fact that the export price of the domestic industry has also declined.
  - vi. During 2021-22 there were additional suppliers from China in the global market due to extended shut down and lower demand in China. This led to additional supplies in the global market which normalized the price of resorcinol.
  - vii. SCC has been forced to reduce price in the Indian market due to price war between the applicant and the Chinese producer. This is evident from the fact that the import price

- from Japan remained stable till 2022-23 but the landed price and the selling price of domestic industry declined even in this period.
- viii. The increase in inventories of the applicant is due to overlooking the market dynamics and it being an unreliable supplier.
  - ix. The applicant has been able to increase its market share despite keeping its prices above the prices of subject imports. Thus, the market share of the applicant is not affected due to price of imports.
  - x. The Authority has not provided any reason for absurd movement in the NFA and depreciation of the applicant.
  - xi. While Authority has relied upon the post period of investigation data of the domestic industry, however, landed price and dumping has not been examined for the post period of investigation.
  - xii. The Authority has not analysed the submissions of the other interested parties regarding inefficient technology. The injury to the domestic industry is only due to the production technology used.
  - xiii. The injury to the domestic industry is due to decline in demand. While the applicant may not have suffered volume injury as demand is higher than the capacities of the domestic industry, it lowered its prices to attract customers.
  - xiv. While the Authority has noted that increase in raw material prices due to Russia-Ukraine conflict would impact all producers globally, such increase did not impact SCC as it produces benzene captively. However, the applicant purchases benzene.
  - xv. The applicant did not supply the subject goods in increased quantities in the merchant market when the anti-dumping duty was in force and there was a supply shortage in the market. The applicant remained focused on captive consumption and export market.
  - xvi. The cost of sales of the domestic industry is higher due to its inefficient production process. Imposition of anti-dumping duty will unnecessarily penalize the user industry.
  - xvii. Since there are limited number of producers globally, the market is tightly regulated. Imposition of anti-dumping duty will adversely impact the users in India by inflating the prices of the subject goods.
  - xviii. Levy of 20% anti-dumping duty will increase the cost of downstream product by 13-18%.
  - xix. Benchmark duties were effective in the past which is evident from the fact that these were neither reviewed nor extended as there was no injury to the domestic industry.
  - xx. The importers request that ad-valorem duties should be levied. Since the price of subject goods fluctuate, imposition of fixed or reference price duties will be punitive to the users.
  - xxi. Reso-tar is a by-product of the subject goods and acts as a direct 1:1 substitute for the subject goods in the production of certain resins. The applicant uses it captively and does not sell it in the merchant market. The Authority may check the cost of domestic industry and whether recovery of such cost has been considered.

**H.2. Submissions by the domestic industry**

133. The domestic industry has made the following submissions on the disclosure statement issued:

- i. There appears to be an error in calculation of non-injurious price while comparing with the claim of domestic industry in terms of methodology in deriving per unit cost of utility, treatment of export incentive and calculation of working capital for the PUC.
- ii. The applicant had provided evidence with regard to post invoicing discounts and compensatory agreements entered into by the producers in the subject countries. The applicant requests that the same should be considered.
- iii. The applicant has expanded capacities prior to the injury period and is planning further capacity expansion. However, the subject goods are capital intensive in nature, and the present market situation is not conducive of any further investments.
- iv. The domestic industry has been forced to export the subject goods due to lack of market of its product in India. Even after selling at losses and exporting the subject goods, the inventories of the domestic industry have increased.

**H.3. Examination by the Authority**

134. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post- disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with evidence have been considered relevant by the Authority are examined below.

135. With regard to the submissions of the other interested parties, that the applicant has not disclosed the evidence of adjustment in export price, the Authority notes that for the purpose of the present investigation, the Authority has determined export price based on the response filed by the cooperating producer. Further, the adjustments made to export price were specified in the Disclosure Statement.

136. The other interested parties have submitted that the Authority has not provided the reason for disparity between the import volume filed by the applicant and that considered by the Authority, the Authority notes that while the applicant has relied on its market intelligence for assessing the volume of imports, the Authority has relied upon DG Systems data in the disclosure statement issued.

137. As regard the submissions that the prices in Japan are higher due to SCC being the sole producer and supplier in the country, the Authority notes that no cogent evidence of the same was provided by the producer. Further, the producer did not provide any evidence to demonstrate that the prices in the domestic market are inordinately high. Mere fact that a producer is a sole producer in the country cannot be considered as resulting in prices being overstated, as the product can always be imported into the country, in competition to the domestic goods. Therefore, the fact that a sole producer exists in the market does not imply

absence of competition. In view of the same, the Authority does not find any merit in the arguments of the interested parties in this regard.

138. As regard the submissions that price undercutting has not been determined for the injury period as a whole, the Authority notes that the price undercutting is determined only for the period of investigation as that dumping and injury to the domestic industry is determined with respect to POI, and trends of injury are determined for the injury period. Further, the Authority has examined price suppression and depression for the injury period as a whole.
139. With regard to the submissions that normalization of market is evident from the fact that the export price of the domestic industry has declined, the Authority notes that the prices in China PR and Japan are higher than that in India which is evident from the response filed by the producers from the subject countries. In such a situation, even if the prices globally have declined, there is evident dumping in the Indian market. The Authority further notes that the domestic industry has exported the subject goods at prices above its cost of sales while it has sold the subject goods in the domestic market at prices below its cost of sales. Thus, the domestic industry is still earning profits in the export market. In such a case, the injury to the domestic industry is due to dumping in India and not due to normalization of market.
140. With regard to the submissions that there were additional supplies in 2021-22 due to shutdowns and decline in demand in China PR, the Authority notes that there is no evidence of decline in demand in China PR. Further, even if there was a decline in demand in 2021-22, there is no evidence of such decline in the period of investigation which would have led to decline in prices in India. Further, it is evident from the responses filed by the producers in the subject countries that such producers are dumping the subject goods in India. Thus, the decline in prices in the Indian market is due to dumping.
141. As regard the submissions that SCC has been forced to reduce prices due to price war between the domestic industry and Chinese producers, the Authority notes that the landed price from Japan is lower than that from China. In such a case, it cannot be concluded that the decline in price from SCC is due to decline in prices from other producers. In any case, the producer from Japan is dumping in the Indian market which is evident from the fact that dumping margin is positive and significant based on the response filed by the said producer.
142. With regard to the submissions that the producers in the subject countries are providing post invoicing discounts and have entered into compensatory agreement, the Authority notes that the information filed by the cooperative producers has been verified. The Authority has determined dumping margin based on the verified data.
143. The other interested parties have submitted that there has been no impact of import price as the domestic industry has been able to increase its market share even though its selling price is above the import price. The Authority notes that the domestic industry has sold at losses during the period of investigation. Due to sales at losses, the domestic industry has been able to increase its market share. Even though the domestic industry has sold at losses, its inventories have increased over the injury period.

144. As regards the submissions that the inventories of the domestic industry have increased due to overlooking the market dynamics and being an unreliable supplier, the Authority notes that in a situation where the market share of the domestic industry has increased, it cannot be considered that the domestic industry was an unreliable supplier. Further, there is ample demand in the market for the domestic industry to utilise its complete capacities. However, even though it has not utilised its total capacities, the inventories have increased. Even though the domestic industry has sold at losses, its inventories have increased as the landed price was undercutting the prices of the domestic industry. This shows that the domestic industry is unable to sell its product in the Indian market due to dumping in India.
145. With regard to reliance on post period of investigation data, the Authority notes that the domestic industry has suffered material injury due to dumping during the period of investigation. Thus, there is no need for examination of data post period of investigation.
146. With regard to the submissions that the cost of the domestic industry is due to obsolete production process, the Authority notes that the domestic industry has submitted that the production process followed by it is stable, efficient and more environment friendly. Further, it has been submitted that the capex investment in the sulphonation fusion process is lower. Further, as per the evidence on record the raw material cost of the applicant is lower by ₹ [ \*\*\* ] per kg as compared to SION norms. Thus, it cannot be said that the production process of the domestic industry is inefficient. Further, as noted in the relevant paragraphs, the domestic industry has not suffered injury in any of the previous years even though it was using the same production process.
147. As regard the submissions that the injury to the domestic industry is due to decline in demand leading to decline in selling price of the domestic industry to attract customers, the Authority notes that the decline in selling price of the domestic industry is due to dumping in India. The landed price of the subject imports is undercutting the prices of the domestic industry. Since the subject goods are a commodity product, the domestic industry has been forced to reduce prices below its cost of sales to retain its market share.
148. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to increase in price of raw material due to Russia-Ukraine conflict, the Authority notes that the raw material cost of the domestic industry has declined in the period of investigation. The difference between the landed price and raw material cost has declined. Thus, the injury to the domestic industry is not attributable to increase in raw material cost.
149. With regard to increase in depreciation and NFA, the Authority notes that it has verified the methodology for allocation and apportionment of expenses and finds that these are in accordance with the principles of Annexure III to the Anti-Dumping Rules and as per the General Cost Accounting Principles. Further, as noted in the relevant part, the injury to the domestic industry is not due to increase in depreciation as PBDIT, which does not account for depreciation and interest, has also declined.



150. The other interested parties have submitted that the market share of the domestic industry did not increase even though there was shortage in the market and anti-dumping duty was in force. The Authority notes that there is no evidence on record to show that the market share of the domestic industry did not increase at that time. Further, there is a demand-supply gap in India. Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India. Thus, even if the market share of the domestic industry does not improve, it will be able to sell its product at fair prices post imposition of anti-dumping duty.
151. As regard the submissions that there are a limited number of producers in the Indian market and imposition of anti-dumping duty will inflate the costs of the downstream industry, the Authority notes that the downstream industry in India have access to the subject goods at prices much less than the price of the subject goods in other countries. This is evident from the fact that the producers in subject countries are selling the subject goods at prices higher than price of imports into India. Imposition of anti-dumping duty will not lead to any disadvantage to the downstream industry in India. On the other hand, imposition of anti-dumping duty will remedy the injury to the domestic industry. Since there is only a single producer in India, it is essential to maintain the viability of such producer.
152. With regard to the submissions that imposition of anti-dumping duty will lead to 15-18% increase in the cost of the downstream product, the Authority has already noted in the relevant section that the downstream industry is pass through in nature. In such a situation there will be no impact on the downstream industry. Further, there is no evidence on record that the anti-dumping duty previously levied on the product under consideration adversely impacted the downstream industry. The Authority also notes that the price of the subject goods was higher in the past. However, there is no evidence of adverse impact on the performance of the downstream industry during such period.
153. The Authority notes that as per the evidence on record, the applicant had expanded capacities prior to the injury period. Further, the applicant has provided evidence showing its intention to expand capacities further. The applicant has submitted that an investment of ₹ [ \*\*\* ] Crores or ₹ [ \*\*\* ] Lakhs per MT is required in order to set up a new brownfield plant for production of subject goods. Since the applicant has suffered financial losses as well as cash losses during the period of investigation, the present market situation is not conducive of any further investment.
154. With regard to error in calculation of non-injurious price (NIP) while comparing with the claim of domestic industry in terms of methodology in deriving per unit cost of utility, treatment of export incentive and calculation of working capital for the PUC, the Authority notes that the non-injurious price has been determined based on the data relating to cost of production provided by the domestic industry for the POI and injury period which was duly verified on sample basis, applying the principles of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995. For determining the NIP, the best utilisation of the production capacity, raw materials and utilities has been considered

over the injury period. As regards methodology for determination of working capital for the PUC, the consistent practice of the Authority to determine working capital for PUC in case of multi product company, has been followed in this case.

155. With regard to the form of anti-dumping duty, the Authority has recommended imposition of benchmark form of duty in the present investigation. Such form of duty will ensure fair prices are restored in India and the injury to the domestic industry is remedied.
156. With regard to the submissions that the Authority should verify the recovery of by-product, the Authority notes that the domestic industry has consumed the by-product captively. The Authority has determined the cost of production of the domestic industry after taking into account the credit for such by-product.

## **I. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS**

157. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- i. The product under consideration is Resorcinol, also known as 1,3-benzenediol; 1,3-dihydroxybenzene; 3-Hydroxyphenol; Resorcin Meta-Dihydroxybenzene in the market parlance and has a chemical formula  $C_6H_6O_2$ .
  - ii. The product under consideration can be produced either using Suphonation fusion process, Hydroperoxidation process or MPDA Hydrolysis process. However, there are no differences between the characteristics of the final product whether produced using Sulphonation-fusion, Hydroperoxidation, or MPDA hydrolysis processes.
  - iii. The domestic industry has produced like article to the subject goods being imported into India. The Authority notes that despite there being different manufacturing processes for the production of the subject goods, the end product is used interchangeably.
  - iv. The applicant had imported a negligible quantity of the product under consideration from its related entity in China PR during the injury period for research and development purposes. Since such imports were negligible in quantity and were made prior to the period of investigation, the Authority holds that such imports do not hamper the eligibility of the applicant to constitute domestic industry for the purpose of the present investigation.
  - v. The applicant is the sole producer of the subject goods in India and thus, accounts for entire domestic production in India. The applicant constitutes domestic industry as per Rule 2(b).
  - vi. The Authority has relied upon the DG Systems data for the purpose of the present investigation.
  - vii. The dumping margin for all producers from the subject countries is positive and significant.
  - viii. The Authority has undertaken cumulative assessment of injury as all the conditions of cumulative assessment have been met in the present investigation.

- ix. The domestic industry has suffered material injury due to dumping in India. The same is evident from the following.
- The volume of subject imports increased till 2022-23, but declined in the period of investigation. However, the volume of imports in the period of investigation was higher than the volume of imports in the base year.
  - The subject imports account for entirety of imports into India.
  - The price undercutting from all subject countries is positive and significant.
  - The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. While the cost of sales of the domestic industry has increased, the selling price have declined over the injury period due to decline in landed price of imports. While both cost of sales and selling price of the domestic industry has declined in the period of investigation as compared to the previous year, decline in selling price was more than the decline in cost of sales.
  - The domestic industry has been forced to reduce its selling prices to a point below its cost of sales.
  - The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period.
  - The cash profit and return on capital employed of the domestic industry have also declined over the injury period.
  - The domestic industry has incurred financial losses and cash losses during the period of investigation.
  - The domestic industry has recorded a negative return on capital employed during the injury period.
  - The prices of the domestic industry have been adversely impacted due to subject imports which are priced below the cost of sales of the domestic industry.
  - The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted as the domestic industry has incurred financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed.
- x. The landed price of imports is below the non-injurious price of the domestic industry. The injury margin determined is positive and significant.
- xi. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market. No other known factor has caused injury to the domestic industry.
- xii. There is no evidence of impact of COVID-19 or the shutdown of the producer in the US on the performance of the domestic industry.
- xiii. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest. The Authority notes the following in this regard.
- Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry.
  - The product under consideration is a commodity product, allowing users to switch suppliers as required.
  - The domestic industry has the capacity to cater to [\*\*\*%] demand in India, however, its share has remained below \*\*\*%.
  - The subject goods are produced globally by only three producers. Given the lack of sufficient alternate sources of supply, maintaining the economic viability of the domestic industry is of critical importance.

- e. Demand-supply gap does not justify dumping. In any case, the imports are in excess of the demand-supply gap.
- f. Imposition of anti-dumping duty will not restrict imports into India.
- g. The domestic industry has already expanded capacities prior to the injury period. The domestic industry has further plans of capacity expansion.
- h. The current market situation is not feasible for fresh investment. In case, the situation is not remedied, the domestic industry will be forced to cease production which will lead to increase in the demand-supply gap in India.
- i. In case of cessation of production by the domestic industry, the Indian importers will be totally dependent upon imports as there will be no source of domestic supply in the country.
- j. The downstream industry can import the subject goods from the subject countries under advance authorization scheme for exporting the downstream product. Hence, the users will not become uncompetitive in the global market.

158. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

159. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duties on import of subject goods originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central government, as the difference between the landed value of subject goods and the reference price indicated in column 7 of the table below, provided the landed value is less than the value indicated in column 7.

**Duty Table**

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of export	Producer	Reference price	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2907 21 00	Resorcinol	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Hongsheng Chemical Co., Ltd.	6244	MT	USD

2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than that mentioned at S.N. 1	6244	MT	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than China PR and Japan	China PR	Any	6244	MT	USD
4.	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	6244	MT	USD
5.	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any other than that mentioned at S.N. 4	6244	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any Country other than China PR and Japan	Japan	Any	6244	MT	USD

160. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act

**J. FURTHER PROCEDURE**

161. An appeal against the order of the Authority arising out of the final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority